सुबह सवेरे

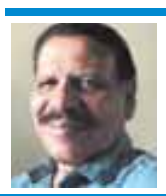

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 349, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

फिर भी गरीब व मध्यवर्ग पर क्यों भारी पड़ा इलाज का खर्च?

इक़बाल हिंदुस्तानी

नेशनल हेल्थ एकाउंट के अनुसार भारत में हर साल महंगे इलाज के कारण 3 से 6 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी की रेखा से नीचे या उसके करीब पहुंच जाते हैं। पहले यह आंकड़ा 5.5 से 10 करोड़ तक आंका जाता था लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होने, उनके जागरूक होने पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ने और सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना से बड़ी संख्या में लोगों को हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च में कुछ राहत मिली है। नीति आयोग का कहना है कि हर साल 2.5 से लेकर 2.7 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा रहा है।

सरकार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या इस समय देश में 45 करोड़ से अधिक हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि 12.69 करोड़ लोग इस योजना के तहत हर साल पांच लाख रूपये तक का अब तक निशुल्क उपचार का लाभ ले चुके हैं। समस्या यह है कि सरकार की यह योजना गरीब वर्ग के लिये होने से मीडियम क्लास के लगभग 40 करोड़ लोगों को इससे कम ही लाभ मिला है। दरअसल, बीमारी किसी की आय नहीं देखती अगर किसी को अचानाक गंभीर बीमारी में अस्पताल में भर्ती होकर आईसीयू में जाना पड़े, हार्ट ऑपरेशन या कैंसर होने पर कीमियोथेरेपी करानी पड़े तो उस परिवार पर इतना अधिक आर्थिक बोझ आ जाता है कि उसका मासिक बजट गड़बड़ा जाता है।

जहाँ विकसित देशों में नागरिक स्वास्थ्य खर्च का मात्र 20 प्रतिशत स्वयं वहन करते हैं वहीं हमारे देश में यह आंकड़ा 45 से 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। जबकि विकसित देशों में लोगों की आय का स्तर भी हमसे काफी अधिक ही है। गंभीर बीमार होने, हार्ट अटैक, ब्रेन हेम्रेज, लकवा, एक्सीडेंट या कोई और ज़रूरी ऑपरेशन कराने के लिये एक बार निजी अस्पताल में भर्ती होने पर कम से कम 50 हजार रू. खर्च आता है। चाइल्ड बर्थ में सीज़ेरियन केस होने पर यह खर्च और अधिक हो जाता है। सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत सबको पता ही है वर्ना यहां यह खर्च 6500 तक ही होता है। सरकार जीडीपी का मात्र 1.5 प्रतिशत ही स्वास्थ्य पर खर्च करती है। थ्री स्टार से फाइव स्टार तक अस्पताल में यही खर्च लाखों रूपये तक पहुंच जाता है। जिसके लिये लोगों को जेवर-ज़मीन-मकान बेचकर या महाजन से ब्याज पर पैसा उधार लेना होता है। इसके बाद ऐसे परिवार लंबे समय तक कर्ज़ के जाल में उलझकर बच्चों की पढ़ाई, मकान का निर्माण और शादी तक को टालने को मजबूर हो जाते हैं।

संसद की एक समिति ने पिछले दिनों महंगे इलाज की शिकायतों को बढ़ता देखकर सरकार से सिफारिश की है कि सभी उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्रों के लिये यह ज़रूरी किया जाये कि वे रोगी को भर्ती करते हुए लंबे इलाज का अनुमानित खर्च उसके परिवार को अनिवार्य रूप से स्पष्ट करें। समिति ने उपचार के मानक, नियम और तौर तरीकों, उपलब्ध सुविधाओं और सभी तरह के खर्च के बारे में भी पारदर्शिता लाने के नियम लागू करने का सुझाव दिया है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में 'वी द पीपुल' संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली जा रही भारी फीस को मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक तरह से लूटना बताया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में वर्तमान कानून को अपर्याप्त बताते हुए नये कानून की ज़रूरत और ऐसे निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा सशर्त दी गयी निःशुल्क ज़मीन लेने के बाद भी गरीब लोगों का सस्ता इलाज नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही पर ज़ोर दिया। सरकार और कोर्ट के रूख से यह पता तो लगता ही है कि महंगा इलाज देश में लोगों के लिये बहुत बड़ी असहनीय समस्या बन चुका है।

एनएसएसओ के एक सर्वे के अनुसार देश में 45 साल से अधिक उम्र के अधिकांश लोग नियमित रूप से दवा खाने को विवश हैं। आंकड़ें बताते हैं कि कुल इलाज का 72 प्रतिशत खर्च केवल दवाओं को खरीदने में ही होता है। इससे देश में दवा उद्योग एक बड़ा कारोबार बन गया है। भारत में आज एक लाख करोड़ से अधिक का दवा व्यवसाय चल रहा है। जिसमें सरकारी दवा कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र 400 करोड़ की है।

हालांकि सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य नियंत्रण के लिये 348 दवाओं के दाम निर्धारित करने का दावा किया है लेकिन इसमें सरकारी अधिकारी और निजी कंपनी के अफसर मिलकर एक खेल यह करते हैं कि उन्होंने किसी भी दवा उत्पाद में एक प्रतिशत से अधिक का हिस्सा रखने वाली ब्रांडेड कंपनियों द्वारा ही निर्धारित किये गये अलग अलग मूल्यों का औसत निकालकर उस दवा का अधिकतक दाम तय कर दिया है। जबकि सबको पता है कि निजी दवा कंपनियां लागत पर 500 से 1000 प्रतिशत तक का मुनाफा वसूल रही हैं।

इसके साथ ही दवा नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी का यह दावा आज भी दावा ही है कि वह दवाओं के दाम निर्धारित सीमित और आम आदमी की पहुँच में रखने के लिये निजी दवा कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिये बाज़ार के हवाले नहीं करेगी बल्कि लागत के हिसाब से दवाओं के रेट तय करने के लिये प्रयासरत है। सरकार दवा बाज़ार का यह सच जानती है फिर भी उनको बेकाबू छोड़ दिया गया है।

कॉरपोरेट मंत्रालय की लागत लेखा शाखा ने अपनी एक स्टडी में यह पाया है कि देश की अधिकांश दवा कंपनियां दवाओं की लागत में 1100 प्रतिशत तक का लाभ जोड़कर दवाओं को बेच रही हैं। साथ ही सरकार के किसी भी नये कानून, नियमन और रेग्यूलेटर का भी खुला विरोध करती चली आ रही हैं। अदालतों ने इन दवा कंपनियों पर हज़ारों करोड़ का जुर्माना भी लगाया है लेकिन इन ब्रांडेड दवा कंपनियों ने मात्र 250 करोड़ अर्थदंड ही अब तक जमा किया है।

इतना ही नहीं, ये कंपनियाँ नियम-कानून का मजाक उड़ाकर भी दवाओं का निर्माण भंडारण और बिक्री कर रही हैं। साथ ही सरकार से नियामक को कंपनियों के हिसाब से चलने का निर्देश देने की मांग भी कर रही हैं। सरकार का रूख़ भी इस मामले में निजी दवा कंपनियों के बेकाबू दवा के दामों को लेकर कोई बहुत आशावादी या सकारात्मक नहीं लगता क्योंकि वह भी पूंजीवादी बाज़ारवादी और मुनाफाखोरी नीति आज के दौर में अपरिहार्य मानकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महंगे इलाज के लिये इनके ही रहम ओ करम पर छोड़ चुकी है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मप्र-उप्र में 'जल' जला

● रीवा और सतना जिले के कई गांवो का संपर्क टूटा ● प्रयागराज में 5 फीट पानी भरा, 2000 स्टूडेंट्स फंसे

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतना में भारी बारिश से चित्रकूट की गुप्तगोदावरी में जलस्तर बढ़ गया। डिंडौरी में नदी-नाले उफान पर हैं और 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। पन्ना के कई गांवों में भी पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चार दिनों से बारिश हो रही है। पिछले तीन दिन में 205 मिमी पानी गिरा। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया। घरों-हॉस्टल में पानी भर गया। बुधवार को करीब 2000 छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। आज भी 9 जिलों में रेड अलर्ट है।

● उत्तराखंड में 4 लोगों की मौत, हर ओर पानी ही पानी

चित्रकूट में सड़कों पर चलीं नाव, रीवा-सतना में बस्तियां डूबीं

मध्य प्रदेश में मानसून फिर ऐक्टिव हो गया है। मऊगंज में अष्टभुजा नदी उफान पर है। बाढ़ से नईगढ़ी गांव डूब गया। यहां अमृत योजना के निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूर फंस गए, जिनमें एक तेज बहाव में बह गया। वह करीब 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं तक के स्कूल गुरुवार को बंद रहे। खरमेर नदी का पानी पुल के ऊपर आने से डिंडौरी-मंडला स्टेट हाईवे बंद हो गया है।

काशी में छतों-गलियों में अंतिम संस्कार, मंदिर-पेड़ नदी में समाए

यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 84 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार बंद कर दिया गया। मणिकर्णिका-हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल जलमग्न हो गए। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रयागराज में 4 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं।

मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपये निवेश की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का किया शुभारंभ

मप्र में तेजी से हो रहा है नई औद्योगिक इकाइयों से युवाओं को रोजगार देने का कार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विकास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2014 के पहले के भारत और उसके बाद के भारत में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। आज भारत का नवीन स्वरूप पूरी दुनिया के सामने उभरकर आया है। मध्यप्रदेश भी इसी विकास यात्रा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित 2 आधुनिक औद्योगिक इकाइयों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से प्रारंभ हुई नई औद्योगिक इकाइयां विकास और समृद्धि की नई धारा को आगे बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपये निवेश की प्रताप ग्रुप की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों कॉर्सिस इंडस्ट्रीज एवं वोल्टर्स टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। इन इकाइयों से सैकड़ों युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती नीना वर्मा, श्री निलेश भारती, प्रताप ग्रुप के चेयरमैन श्री देवेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमती मानकुंवर, डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रताप ग्रुप श्री शक्ति सिंह, श्री मोहन शेखावत, श्री प्रपन्ना आदि भी मौजूद थे।

युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से शुरू हुई दोनों इकाइयां उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्यप्रदेश भी युवा शक्ति से समृद्ध है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी जैसी आधुनिक तकनीक से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम है।

पाकिस्तान को झटका, देखते रह गए अमेरिका और चीन

● भारत और जापान के बीच हो गई है अहम डिफेंस डील

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में इसके लिए एक द्विपक्षीय बैठक की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इस समझौते के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग मजबूत होगा, जिसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना शामिल है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बड़ी डील

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने फी और खुले हिंद-प्रशांत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा सहयोग और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर एक-दूसरे के आकलन साझा करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता और सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया।

भारत-जापान के डिफेंस मिनिस्टर की द्विपक्षीय मीटिंग

दोनों पक्ष समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाजों और सैन्य इकाइयों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ाएंगे। संयुक्त अभ्यास, सैन्यकर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान भी होगा। बंदरगाहों, रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौसैनिक जहाज निर्माण में सहयोग की संभावना को भी बढ़ाया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।

सुप्रभात

आज और कल में
यही बदलाव हुआ
आसमान मेरे सिर पर थोड़ा झुक गया
मेरे पांव के नीचे की जमीन सिकुड़ गई
सड़के अजनबी लगने लगी
दरख्तों के नाम और पता बदल गया
आज और कल में यही बदलाव हुआ
मेरे मोहल्ले के कुत्ते बेनाम हो गए ।
जो वर्तमान के हत्यारे थे
वही आज साकेत में बैठकर
दिल्ली को आँख दिखा रहे है
जो दिल्ली में बैठे हुए हैं
वह लोग राम के नाम पर नया
महाकाव्य लिख रहे हैं।

– नीतीश मिश्र

अब एक रजिस्ट्रेशन से कहीं भी प्रैक्टिस कर पाएंगे डॉक्टर!

मिलेगी एक यूनिक आईडी, नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा। प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और डॉक्टर के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज रहेगी। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे। यह प्रस्ताव डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े 2026 के ड्राफ्ट नियमों में रखा गया है। राज्य मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एनएमआर का एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टर को आईडी जारी करेगा। आईडी मिलने के बाद डॉक्टर का नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) में दर्ज होगा। यही आईडी देशभर में डॉक्टर की पहचान के तौर पर काम करेगा और उसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। प्रस्ताव के मुताबिक, डॉक्टर का प्रैक्टिस लाइसेंस 5 साल तक वैध रहेगा।

डॉक्टर पर कार्रवाई भी पूरे देश में दिखेगी

एनएमआर में डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और अनुशासनात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर किसी डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही, गलत आचरण या पेशेवर कदाचार का मामला सामने आता है, तो संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल उसकी जांच करेगी। अगर किसी दूसरे राज्य की काउंसिल डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो इसकी जानकारी एनएमआर में भी अपडेट होगी।

अब सबसे ऊंचे रेल पुल पर फर्राटा भरेगी वंदे भारत ट्रेन

बढ़ाई गई स्पीड, अब 100 किमी प्रतिघंटे की होगी रफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया में सबसे ऊंचा रेल पुल भारत में है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच चिनाब नदी पर बना है। इसलिए लोग इसे चिनाब ब्रिज भी कहते हैं। इसकी नदी के तल से ऊंचाई 369 मीटर है जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल पर वंदे भारत एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। जी हां, रेलवे ने कटड़ा से बनिहाल के बीच रेलगाड़ियों की अधिकतम गति 100 किमी प्रतिघंटा कर दी है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 21 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

एनएच-43 चौड़ीकरण मामले में एमपी हाईकोर्ट का कड़ा रुख

किसानों को 10 दिन में मुआवजे का आदेश

अनूपपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के किसानों के पक्ष में एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। साल 2016-17 के दौरान एनएच-43 (एनएच-43) के चौड़ीकरण के लिए जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थीं, उन्हें अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया था। इस मामले में अब अदालत ने एनएचएआई और एमपीआरडीसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों एजेंसियों के बीच अपने आपसी वित्तीय हिस्से या विवाद के कारण किसानों के मुआवजे में देरी नहीं की जानी चाहिए।

आपसी विवाद में नहीं फंसेगा किसानों का हक

जस्टिस विवेक कुमार अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दोनों एजेंसियां अपने आपसी मुद्दों को बाद में सुलझाती रहें, लेकिन किसानों का भुगतान तुरंत किया जाए। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन तय समयसीमा के भीतर नहीं किया गया, तो अनूपपुर कलेक्टर और दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी।

क्या है पूरा मामला और लापरवाही?

ज्ञान सिंह समेत करीब 10 किसानों ने लंबे समय से रुके पड़े मुआवजे के भुगतान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि इस प्रशासनिक लापरवाही और देरी के चलते तत्कालीन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कोतमा के एसडीएम मिलिंद नागदेव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

- साल 2016-17 में एनएच-43 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था।
- समय पर मुआवजा न मिलने पर किसानों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
- कोर्ट ने एजेंसियों के आपसी विवाद को किसानों के हक में रुकावट बनने से मना कर दिया है।
- तय समय में भुगतान न होने पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इमरान हाशमी की 'जन्नत' देख बुकी बनने चले थे नीट स्टूडेंट

सागर में ऑनलाइन सट्टे का महा-खुलासा, 2.96 करोड़ कैश और सोना बरामद

सागर (नप्र)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक विशाल और संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने सागर और भोपाल से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी और करीब 30 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़े लेनदेन की शिकायत के बाद कड़ियां जुड़नी शुरू हुईं, जिसके बाद पुलिस ने इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दिया।

पंचर वाले के खाते से खुला करोड़ों के खेल का राज- मामले की शुरुआत तब हुई जब एक साधारण पंचर बनाने वाले व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की कि उसके बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपये का लेनदेन हो रहा है। इतनी बड़ी रकम के ट्रांजेक्शन से परेशान होकर उसने पुलिस की शरण ली। इसके बाद पुलिस ने बैंक खातों की तकनीकी जांच शुरू की और लेनदेन की कड़ियों को जोड़ते हुए मुख्य सट्टेबाजों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

वेबसाइट्स और किराए के खातों का होता था इस्तेमाल- जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन वेबसाइटों के जरिए लोगों को सट्टा खिलाते थे और सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से टिप्स भी देते थे। इसके अलावा, पैसों की जरूरत वाले बेरोजगार और कम पढ़े-लिखे लोगों को 500 से 1000 रुपये का लालच देकर उनके दस्तावेज लिए जाते थे, जिनका उपयोग बैंक खाते खुलवाने में किया जाता था।

जन्नत फिल्म देखकर बने बुकी, NEET की तैयारी कर रहे थे छात्र- इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू आरोपियों की पृष्ठभूमि है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए अमित विश्वकर्मा और ऋषभ पटेल ने खुलासा किया कि वे नीट की तैयारी कर रहे थे।

संक्षिप्त समाचार

अमरीका में उठी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग

- आयोग बोला-यहां आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें नहीं करने को कहा है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी मूल के महमूद का यह बयान मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है।

सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन

- अचेत अवस्था में लाया गया था सफदरजंग अस्पताल, हुई मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित किया गया। बहरहाल, सज्जन कुमार की मृत्यु की वजहों को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिख विरोधी दंगों में तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार जेल में ही अचेत हो गए थे। उसी अवस्था में उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सी एम एल आर वर्कशॉप, झांसी की नई पहल

NSG-6 स्टेशनों पर मॉड्यूलर बायो-टॉयलेट लगाए गए

लखनऊ (एजेंसी)। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ-सुथरी और बेहतर सुविधाएँ देने की कोशिशों के तहत, कोच मिडलाइफ रिहैबिलिटेशन (CMLR) वर्कशॉप, झांसी ने एक नई इन-हाउस पहल शुरू की है। वर्कशॉप के तकनीकी स्टाफ ने ललितपुर जिले के माताटीला, जीरोन, जखोरा स्टेशनों और दतिया जिले के बसई स्टेशन पर मॉड्यूलर बायो-टॉयलेट बनाए और लगाए हैं। ये सभी NSG-6 कैटेगरी के स्टेशन हैं।इस पहल की मुख्य बात यह है कि इसमें कोच की पीरियडिक ओवरहॉलिंग के दौरान निकले काम के और दोबारा इस्तेमाल होने लायक पार्ट्स का प्रभावी तरीके से प्रयोग किया गया है। इन पार्ट्स में फाइबर-रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट मॉड्यूल, बायो-टैंक, पानी की टंकियाँ और कोच के दूसरे दोबारा इस्तेमाल होने लायक सामान शामिल हैं।इन पार्ट्स को कबाड़ समझने के बजाय, दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उनकी जाँच की गई, उन्हें साफ किया गया, मरम्मत की गई और जहाँ ज़रूरत थी सुधारा गया। इस तरह, यह पहल मौजूदा रेलवे संसाधनों के सबसे अच्छे इस्तेमाल की दिशा में एक असरदार कदम है और 'वेस्ट टू वेल्थ' के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है।

कर्मचारी हेल्थ स्कीम पर 7 साल से फैसला नहीं

बिना बजट लागू हो सकती है योजना, पुलिस चिकित्सा मॉडल लागू करने की उठ रही मांग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख कर्मचारियों और साढ़े 4 लाख पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित कर्मचारी हेल्थ स्कीम पर 7 साल बाद भी फैसला नहीं हो सका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि योजना में सरकार पर कोई खर्च नहीं आएगा, क्योंकि बीमा का प्रीमियम कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन से काटा जाएगा।

साल 2019 से इस योजना को लेकर बैठकें और प्रस्ताव होते रहे हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार चाहे तो पुलिस कर्मियों के लिए लागू चिकित्सा बीमा योजना के मॉडल को अपनाकर भी राहत दे सकती है।

2019 में शुरू हुई थी योजना की प्रक्रिया- मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को चिकित्सा बीमा योजना में शामिल करने का मामला 2019 से लंबित है। उस समय अनुराग जैन अपर मुख्य सचिव वित्त और पल्लवी जैन गोविल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थीं। शासन की ओर से ही योजना की प्रक्रिया शुरू की गई थी और सभी ने इसका स्वागत किया था। उस समय कोरोना का दौर था और लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी बढ़ी थी। इसलिए इस

योजना को समय की जरूरत माना गया था। अनुराग जैन बाद में दिल्ली गए और प्रदेश के मुख्य सचिव रहते हुए दोबारा भारत सरकार में चले गए, जबकि पल्लवी गोविल भी अब भारत सरकार में हैं। इसके बावजूद योजना 7 साल बाद भी लागू नहीं हो सकी।

बैठक में कर्मचारी संगठनों से लिए थे सुझाव- अनुराग जैन ने वर्ष 2019 में एसीएस और सीएस रहते हुए प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों की बैठक मंत्रालय में बुलाई थी। इसमें कर्मचारी संगठनों को योजना की जानकारी दी गई और उनके सुझाव भी लिए गए थे।

आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है।

मंत्रालय सेवा अधिकारी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के मुताबिक, योजना में सरकार पर कोई व्यय भार नहीं आएगा। चिकित्सा बीमा का प्रीमियम कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन से कटेगा, जबकि दावों का भुगतान उस कंपनी की ओर से किया जाएगा, जिसे इसका ठेका मिलेगा। नायक का कहना है कि 7 साल में यह समझ नहीं आया कि योजना लागू करने में दिक्कत कहां आ रही है। बार-बार बैठकें और घोषणाएं होती हैं, लेकिन आदेश जारी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस का सेक्टर अब काफी विकसित हो चुका है। केंद्र सरकार और कई निजी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए ऐसी योजनाएं चल रही हैं, इसलिए उनके अनुभवों का डेटा भी आसानी से उपलब्ध है।

पुलिस में 60 रुपए में 5 लाख का बीमा- मध्यप्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए वर्ष 2013 से चिकित्सा बीमा योजना चल रही है। इसमें 60 रुपए मासिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर दिया जाता है।नायक के मुताबिक, 2013 में जब पुलिस कर्मियों के लिए यह योजना लागू हुई थी, उसी समय इसे सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता था। उस समय सभी कर्मचारियों के लिए इसे लागू क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। पुलिस की योजना में निजी बीमा कंपनियों की तुलना में काफी कम प्रीमियम लिया जाता है। इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग ने किसी कंपनी को ठेका देने के बजाय एक विभागीय समिति बनाकर योजना का संचालन कराया है। इससे कंपनी को मिलने वाला मुनाफा बच जाता है और प्रीमियम कम रहता है।

इसी मॉडल पर कर्मचारी हेल्थ स्कीम लागू करने का सुझाव है। अगर इसमें दिक्कत हो तो किसी कंपनी को ठेका

20 लाख लोगों से प्रीमियम आने का अनुमान

मोटे तौर पर 10 लाख नियमित और गैर-नियमित कर्मचारी हैं और लगभग इतने ही पेंशनर्स हैं। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि 20 लाख लोगों के इस बड़े समूह से इतना प्रीमियम आएगा कि कुछ वर्षों बाद शासन को आय भी होने लगेगी। इसके साथ ही निगरानी जरूरी होगी, ताकि अस्पतालों की मिलीभगत से फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर दावे न किए जाएं। इस तरह की शिकायतें आयुष्मान योजना को लेकर भी सुनने में आती हैं। शासन से एक बार फिर मांग है कि इस योजना को बिना किसी व्यय भार के लागू किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी

मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के अलावा मप्र लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और मप्र राज्य कर्मचारी संघ समेत प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन कर्मचारी हेल्थ स्कीम जल्द लागू करने की मांग कर चुके हैं।

कुछ संगठनों ने अगस्त में इसे लेकर प्रदर्शन भी किया है। साथ ही अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि योजना लागू नहीं होने का असर प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स पर पड़ रहा है।

दिल्ली में पाक हाई कमीशन के बाहर चल गया बुलडोजर

- बैरिकेड-फेंसिंग हटाई गईं, दो दिन पहले इस्लामाबाद में हुई थी कार्रवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, ये

अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी-पंडाल की साज सज्जा करें : मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। गणेशोत्सव त्यौहार (14 सितम्बर) तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों ने व्यवस्थित प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली साज-सज्जा,नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

अस्थाई कनेक्शन लेने के लिये क्या करें- बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झाँकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी।

कांग्रेस का पूरा

- शाह बोले-उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर पाप किया

फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और

शाह ने कहा- कांग्रेस देश का कानून नहीं मान रही

अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का सिर्फ दो पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फैसले को फिर लागू कर रही है।

नितिन नवीन बोले- कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई

वंदे मातरम विवाद पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। यह फैसला वंदे मातरम को अपने मन में रखकर बलिदान देने वाले शहीदों का अपमान है। वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की।

उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद

- 600+ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, बचाव के लिए लोग डंडा लेकर निकल रहे

चमोली (एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में हिंसक कुत्तों के हमलों से अब तक 11 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इन स्कूलों के 600 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। कुत्तों के डर से लोग घर से बाहर जाते समय हाथ में डंडा लेकर निकल रहे हैं। चमोली कलेक्टर गौरव कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया था। पहले 20 से 23 अगस्त तक चार दिन की छुट्टी की घोषणा हुई।

17 सदस्यीय जॉइंट टीम चला रही ऑपरेशन

क्विक रिस्पॉन्स टीम में वन विभाग के 5, पशुपालन विभाग के 4 और तहसील के 4 कर्मचारी हैं। टीम के साथ 2-3 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। अभियान की निगरानी एसडीएम यदवीर सिंह कर रहे हैं। कुत्तों को जाल की मदद से पकड़ा जा रहा है। पशुपालन विभाग ने नारायणबगड़ पशु चिकित्सालय में 2 कैंप शुरू किए हैं। पकड़े गए कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोगों से अपने कुत्तों का टीकाकरण कराने के लिए भी कहा जा रहा है।

भारत को गाजा की चिंता, वेस्ट बैंक में बना रहा हॉस्पिटल

इजरायल से दोस्ती के बावजूद नई दिल्ली का प्लान कर रहा हैरान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और फिलिस्तीन के बीच बड़ा डेवेलपमेंट सामने आया है। भारत विकास के लिए फिलिस्तीन को मुहैया कराई जाने वाली मदद को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसी क्रम में, बुधवार को दोनों पक्षों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 200 बिस्तरों वाले भारतीय सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने का ऐलान किया। इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और एक ट्रॉमा सेंटर भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलिस्तीन के राजदूत

अब्दुल्ला अबू शावेश ने बुधवार को 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया। पत्रकारों से बात करते हुए शावेश ने कहा, जब हम व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते थे, तो एक साउदर्न देश यानी विकासशील देश के तौर पर हमारी एक अपील यह थी कि भारत उन देशों में शामिल हो जिनके पास परिषद में स्थायी सीट हो।

फिलिस्तीन के साथ करार पर हस्ताक्षर का ऐलान

विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा की मुख्य बातों में से एक फिलिस्तीनी नेशनल प्रिंटिंग प्रेस के भीतर एक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करना था, जो प्रिंटिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बता दें कि श्रीप्रिया रंगनाथन ने बुधवार को रामल्ला में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात की और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी एवं सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में सचिव (दूतावास सेवा, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले) श्रीप्रिया रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक मिस्र, फिलिस्तीन और लेबनान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार मजदी अल-खाल्दी से भी मुलाकात की और राजनीतिक जुड़ाव तथा विकास सहयोग सहित व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी का जायजा लिया।

राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण

उप मुख्यमंत्री देवड़ा की उपस्थिति में अध्यक्ष पवैया ने किया लोकार्पण

भोपाल (नप्र)। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण आज वल्लभ भवन में किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया ने वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, आयोग के सदस्य श्री के.के. सिंह, श्री वीरेंद्र कुमार तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतें मिलकर व्यापक नागरिक सहभागिता का आधार बनती हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं और सुझाव सीधे शासन तक पहुंचते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब इन सुझावों को आयोग की कार्य प्रणाली में शामिल किया जाएगा, तो इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट से आम नागरिक भी आयोग की गतिविधियों से सीधे जुड़ सकेंगे। लोग अपने सुझाव भी ऑनलाइन दे पाएंगे। उन्होंने आयोग के सभी सदस्यों और अधिकारियों को इस पहल के लिए बधाई दी।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होने से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों को सुविधा

मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने कहा कि यह वेबसाइट भविष्य में अत्यंत उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि आयोग की सूचनाएं, गतिविधियां और अनुशंसाएं अब डिजिटल रूप में आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे सूचना तक पहुंच सरल होगी और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था पर संवाद का प्रभावी माध्यम बनेगा।

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। वह उनके संसाधनों को मजबूत करने के लिए ठोस अनुशंसाएं देगा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट आयोग के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और सुझाव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

वेबसाइट के माध्यम से आयोग की कार्य प्रणाली, गतिविधियां और अनुशंसाएं अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। पंचायतों और नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इससे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

आयोग राज्य के करों, शुल्कों, पथकरों और फीस के शुद्ध राजस्व के वितरण की समीक्षा करेगा। वह राज्य, पंचायतों और नगरीय निकायों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे पर सुझाव देगा। साथ ही, स्थानीय निकायों को मिलने वाले करों और अनुदानों के सिद्धांतों पर भी विचार करेगा। आयोग भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर से प्राप्त राजस्व के वितरण पर भी सुझाव देगा। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त आयोग ऋण दायित्व, ब्याज भुगतान और स्थापना व्यय की सीमाओं पर भी विचार करेगा। वह पूंजीगत व्यय, जन-सुविधाओं के विस्तार और प्रोत्साहन नीति पर भी अनुशंसाएं देगा।

आयोग लेखा परीक्षण व्यवस्था की समीक्षा करेगा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। वह जन-सुविधाओं के संचालन और रखरखाव में व्यय के युक्तियुक्तकरण पर भी सुझाव देगा। वेबसाइट का शुभारंभ राज्य वित्त आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और जन-सुविधाओं से जुड़ी जानकारी अब अधिक सुलभ और प्रभावी रूप से उपलब्ध होगी।

मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य संचालन समिति गठित

भोपाल (नप्र)। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किये गये मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में राज्य शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में सचिव, सहकारिता, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त,खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, संचालक केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल, संचालक, केन्द्रीय मृदा विज्ञान संस्थान नवीबाग भोपाल, प्रदेश प्रभारी नाबार्ड, नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, दलहन एफपीओएस को-ऑपरेटिव्स, वीसीपीएसके दो प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामित दलहन, बीज उत्पादन आदि के दो उद्योग के प्रतिनिधि, भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ राज्य मिशन संचालक को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

समिति राज्य में मिशन की गतिविधियों की देखरेख और संचालन करेगी। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि राज्य एजेंसियों, ज़िला निकायों और केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए, मिशन के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी परिणामों में परिवर्तित किया जाएगा।

राज्य संचालन समिति के दायित्व

मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समग्र नीति दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मिशन कार्यान्वयन की समग्र निगरानी की जायेगी।क्लस्टरों की पहचान और गठन एक बार की प्रक्रिया होगी। एसएससीपी अपनी बैठक में जिलों/क्लस्टरों की स्थिति की समीक्षा करेगा और आवश्यक परिवर्तनों या संशोधनों पर विचार करेगा, जिन्हें एनएससीपी को उनकी समीक्षा और अनुगंदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।राज्य को सौंपे गए एपीवाई लक्ष्यों और उसकी निगरानी के आधार पर दलहन की खेती और उत्पादन के लिए राज्य दलहन कार्य योजना को अंतिम रूप देना,भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण को वार्षिक राज्य कार्य योजना प्रेषित करने के पूर्व मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्य के दृष्टिगत संभावित वार्षिक राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देना,भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण को प्रस्तुत नियमित रिपोर्टों के साथ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर नज़र रखकर राज्य स्तर पर मिशन की प्रगति की निगरानी की जायेगी। समिति द्वारा आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाओं आदि के विकास के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय संसाधन आवंटन की देखरेख करना,जिला मिशनों के कामकाज और प्रगति की निगरानी की जायेगी और उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी करना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करना,मिशन के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और इसे राज्य की कृषि नीतियों और विकास योजनाओं के साथ संरेखित करने के लिए संबंधित विभागों कृषि, सिंचाई, वित्त, ग्रामीण विकास आदि के साथ समन्वय करके अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना,राज्य में मिशन के कुशल क्रियान्वयन के लिए प्रासंगिक मामले और दायित्वों का निर्वहन करेगी। एसएससीपी के अध्यक्ष आवश्यक होने पर अतिरिक्त अधिकारियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। एसएससीपी की बैठक वर्ष में दो बार होगी।

मुख्यमंत्री ने सुश्री प्रज्ञा बघेल को दी बधाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सचिव पद पर पुनर्निर्वाचित हुईं मप्र की सुश्री प्रज्ञा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने पर मध्यप्रदेश की बेटी सुश्री प्रज्ञा बघेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल की मंगलकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने वाली प्रदेश की पहली एडवोकेट के रूप में सुश्री बघेल ने प्रदेश का मान बढ़ाया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश की एडवोकेट सुश्री प्रज्ञा बघेल ने 18 अगस्त 26 को नई दिल्ली में सम्पन्न सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव में सचिव पद के चुनाव में विजय हासिल की है। एडवोकेट सुश्री बघेल, सेवानिवृत्त आई.ए.एस, अधिकारी श्री एल.एस. बघेल की पुत्री हैं। श्री बघेल सतना जिले के रामपुर बघेलान (बम्हौरी) के निवासी हैं।एडवोकेट सुश्री प्रज्ञा ने सिंधिया कन्या विद्यालय,ग्वालियर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुणे के प्रतिष्ठित लॉ कालेज, आई.एल.एस. कालेज से वर्ष 2002 में बी.ए.एल एल.बी. की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना शुरू किया।सुश्री प्रज्ञा स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहीं हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव की सौगात से लाड़ली बहनें मुस्कुराईं : राकेश शर्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश के लाड़ले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के पूर्व ढाई सौ रुपए का तोहफा दिया है। लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। सावन के इस माह में लाड़ली बहनें रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाएं इसलिए उन्हें लाड़ली बहन योजना में प्राप्त हो रही राशि 1500 रुपए के साथ इस माह 250 रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव प्रदेश की बहन-बेटियों की हमेशा चिंता करते हैं। बहन -बेटियों की रक्षा-सुरक्षा एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बहन-बेटियां उठा रही हैं।

बलराम कृषि महोत्सव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा उपस्थित रहे।

निर्मला भूरिया ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनी जनसमस्याएं

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं को सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं की जनसमस्याओं का संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समाधान कराया। जिन प्रकरणों में विस्तृत प्रक्रिया अपेक्षित है, उन्हें संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण के लिए

भेजा गया।

मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान भाजपा सरकार एवं संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कैलारस शुगर मिल चालू कराने एमएसएमई विभाग बुलाएगा टेंडर

कांग्रेस विधायक कर रहे आमरण अनशन, कृषि मंत्री बोले- कारखाना शुरू होगा

भोपाल (नप्र)। मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का 15 अगस्त से आमरण अनशन जारी है। विधायक के आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से कांग्रेस विधायक और नेता कैलारस पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कैलारस जाकर अनशन में शामिल होंगे।

इसी बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने भोपाल में मीडिया से कहा कि सरकार ने कारखाने को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया और भविष्य की योजना सामने रखी है। सरकार का कहना है कि कारखाना शुरू होने से गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बड़े शक्कर मिल संचालकों से मांगे जाएंगे प्रस्ताव- सरकार ने कारखाने को दोबारा संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। कृषि मंत्री के अनुसार एमएसएमई विभाग देश के बड़े शक्कर मिल संचालकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जल्द ईओआई इंटरप्राइजेस

ऑफ इंट्रेस जारी करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही कारखाने के संचालन के लिए जरूरी जमीन अलग रखने के बाद बची भूमि पर विभिन्न एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

विधायक के अनशन से बढ़ी मुद्दे की सियासी अहमियत- एक तरफ विधायक पंकज उपाध्याय कारखाना शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं और कांग्रेस नेता लगातार उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि कारखाने को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि शक्कर कारखाने के दोबारा संचालन के साथ अतिरिक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से मुरैना जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इससे निवेश बढ़ने, नए उद्योग स्थापित होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दर्जनभर से ज्यादा नेता अनशन में शामिल- कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के आमरण अनशन में अब तक सांसद अशोक सिंह, फूल सिंह बरैया, जयवर्धन सिंह, धर्मेंद्र चौहान, अवनीश भार्गव, दिनेश गुर्जर, देवेंद्र सखवार, केशव देसाई, सुरेश राजे, घनश्याम सिंह, मुकेश मल्होत्रा, साहब सिंह गुर्जर, कैलाश कुशवाह, पूर्व विधायक नीटू सिकरवार, रवींद्र तोमर, प्रागीलाल जाटव, मेवाराम जाटव, बैजनाथ कुशवाह, पूर्व मंत्री बालेन्दु शुक्ला और अवधेश नायक समेत कई नेता शामिल हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री दे चुके हैं कारखाना शुरू करने के निर्देश

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन का उपयोग उद्योगों की स्थापना और रोजगार बढ़ाने के लिए करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कारखाने की जमीन MSME विभाग को हस्तांतरित की गई थी।

मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कैलारस शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। कंसाना ने कहा कि कारखाना शुरू होने से क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग कैलारस और आसपास के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेगा, ताकि कारखाने के संचालन के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध हो सके।

पत्नी से विवाद के बाद युवक का सुसाइड

भोपाल (नप्र)। भोपाल के स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र में शराब के नशे में पत्नी से विवाद के बाद एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 44 वर्षीय दीपक रैकवार पुत्र राम प्रसाद रैकवार के रूप में हुई है। वह सेमरा स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दीपक 17 अगस्त की रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी दौरान शराब की लत छोड़ने की बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया। विवाद के बाद उसने घर में फांसी लगा ली।

परिजनों की नजर पड़ने पर उन्होंने तत्काल दीपक को फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

दिव्यांगजन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से बनेगा समावेशी मध्यप्रदेश : मंत्री कुशवाह

भोपाल (नप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन केवल शासकीय योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास की मुख्यधारा के समान सहभागी हैं। एक समावेशी समाज का निर्माण ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यह बात भोपाल स्थित होटल पलाश में न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं साइटसेवर्स इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम Building an Inclusive Madhya Pradesh: A Decade of the RPwD Act and State Disability Polic Dialogue के उद्घाटन सत्र में कही।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करने के लिए संकल्पित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के दस वर्ष पूरे होना देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लागू इस ऐतिहासिक अधिनियम ने देश में दिव्यांगता के प्रति सोच और दृष्टिकोण को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय संवाद इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के अधिकारों, समान अवसर, समावेशी विकास तथा आरपीडीएक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन सहित मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए नीतियों और व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर सार्थक विचार-विमर्श किया गया।

'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प से आगे बढ़ेगा प्रदेश

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास का आह्वान समावेशी विकास की मूल भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुगम्यता और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध हों तथा वे आत्मनिर्भर होकर समाज और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मध्यप्रदेश, जहां दिव्यांगजन केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि समान अधिकारों के साथ विकास की मुख्यधारा के सहभागी हों—यही समावेशी समाज की सच्ची पहचान है।

शासकीय योजनाओं और सामाजिक संस्थाओं की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को जोड़कर बनेगा जॉइंट एक्शन प्लान : राज्यमंत्री गौर

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के विकास पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी तथा सामाजिक संस्थाओं के जमीनी नवाचारों व अनुकरणीय गतिविधियों को समाहित कर एक बहुआयामी जॉइंट एक्शन प्लान निर्मित किया जाएगा, जिससे विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और रोजगार को सीधे जोड़कर आजीविका के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। उन्होंने रेखांकित किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण अभ्युदय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय के पावन ध्येय को साकार करने के लिए शासन और अशासकीय संस्थाएं परस्पर समन्वय स्थापित कर नए रास्तों का निर्माण कर रही हैं।

संचालनालय, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास द्वारा आयोजित

कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी विजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने सभी सहभागियों से समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यशाला में पद्मश्री श्री भीकू रामजी ईदाते, सामाजिक चिंतक श्री गोरेलाल जी, भारत सरकार के डीडब्ल्यूबीडीएनसी संचालक श्री रहीस एम, विकास बोर्ड (अभिकरण) के अध्यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा तथा संचालक श्री बुद्धेश कुमार वैद्य, विभाग के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ तथा प्रदेश भर से आए स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि सीमित संसाधनों और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी सामाजिक संस्थाएं अत्यंत उत्कृष्ट व अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। इन समाजों का इतिहास त्याग, तपस्या और स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान की गाथाओं से परिपूर्ण रहा है; अतः इनके संरक्षण, गरिमापूर्ण जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शासन, प्रशासन और समाज का यह संयुक्त मंच वंचित वर्गों के उत्थान के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। पद्मश्री श्री भीकू रामजी ईदाते ने राज्यमंत्री श्रीमती गौर के संवेदनशीलता से परिपूर्ण एवं चिंतनशील नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के संवाहक और जीवंत संस्कृति के रक्षक रहे इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर घर-घर जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। श्री ईदाते ने महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी आश्रम शालाओं, शोध केंद्रों तथा राज्य, जिला व तहसील स्तर पर संयुक्त समितियों के गठन का दूरदर्शी प्रस्ताव रखा, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक बस्ती के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं अभिकरण अध्यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा ने सघन सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर पात्र नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र व आवास उपलब्ध कराने की दिशा में जारी प्रयासों को रेखांकित किया तथा बस्ती विकास व छात्रावास अनुदान राशि वृद्धि के लिए राज्यमंत्री श्रीमती गौर के प्रति आभार व्यक्त किया।

संपादकीय

गोर के बयान के मायने

जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान और उनके श्रीनगर दौरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान गोर ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर जो बयान दिया, वह भारत के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन उसने पाकिस्तान को भड़का दिया है। कूटनीतिक विश्लेषक इस के कारणों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर ट्रंप सरकार की नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन आया है या फिर यह केवल भारत को खुश करने की नई चाल है? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि गोर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भरोसेमंद अधिकारी समझा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का दौरा किया। गोर साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। उनका यह दौरा तब हुआ है, जब अमेरिकी सरकार ने अपने देश के नागरिकों को कश्मीर न जाने की सलाह दी हुई है, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला से मुलाकात और भ्रमणके बाद जिंयो गोर ने पत्रकारों से बातचीत की में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का 'अहम' हिस्सा है। मैं यहां पर पहली बार आया हूं। उन्होंने कहा कि 'यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह को देखकर बहुत खुश हूं। राज्य के मुख्यइमंत्री से हमारी अभी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमारे कुछ फॉलो-अप्स हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें वॉशिंगटन, दिल्ली वापस ले जाएंगे। लेकिन यह बहुत गर्मजोशी भरा, बहुत अच्छा रहा और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।' गोर ने संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में अपने पर्यटकों को दी गई ट्रैवल एडवायजरी पर फिर से विचार कर सकता है। खास बात यह है कि गोर जब यह बयान दे रहे थे, तब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। अब्दुल्ला ने कहा कि गोर के दौरे से कश्मीर और वाशिंगटन के रिश्ते और मजबूत होंगे। गोर के बयान को आम तौर पर सकारात्मक संकेत के रूप में लिया गया है। फिर भी सोशल मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का 'अभिन्न अंग' कहने की जगह 'महत्वपूर्ण' ही क्यों कहा? हालांकि इस शब्द के साथ उन्होंने यह तो मान ही लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसे कूटनीतिक सावधानी भी माना जा रहा है। अलबत्ता गोर के इस बयान ने पाकिस्तान को भड़का दिया है। उसने तुरंत पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी' अफ़ेयर्स को तलब कर गोर के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक उसने भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दिए गए तथ्यात्मक रूप से ग़लत बयानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को 'भारत का हिस्सा' बताए जाने की कड़ी निंदा की और इसे स्पष्ट रूप से ख़ारिज कर दिया। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार अपने अंतिम समाधान का इंतज़ार कर रहा है। गौरतलब है कि भारत जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। वहीं पाकिस्तान इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के दख़ल की वकालत करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था। दूसरे, हाल में पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। ऐसे में गोर का यह बयान पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है।

नजरिया

तनवीर जाफ़री

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप

उधर ईरान की तरफ़ से संभावित ख़तरे के संदेह में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अंतिम समय में विमान बदलने से जुड़ी हुई एक हैरतअंगेज़ ख़बर सामने आई। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार पिछले महीने तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन से निकलते समय ट्रंप ने गुपचुप तरीक़े से अपना विमान बदल लिया था। ख़बरों के मुताबिक़ अमेरिकी राष्ट्रपति टेलीविज़न कैमरों की मौजूदगी में एयर फ़ोर्स वन में सवार हुए, फिर उन्हें चुपके से एक ऊंचे एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक में ले जाया गया और एक सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। हालांकि, अब वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने एक बार फिर विमान बदल दिया था। पोस्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप को पुराने एयर फ़ोर्स वन विमान से एक कैटरिंग कंटेनर में बाहर निकाला गया। यह कंटेनर ट्रंप को एक छोटे सी-32ए विमान तक ले गया। इसी विमान से उन्होंने ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी। इस दौरान विमान में सवार पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इससे पहले अंकारा में शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान का 'नंबर वन निशाना' हैं।

ट्रंप के ईरान से भयभीत होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जुलाई 2026 में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या से जुड़े बेहद आक्रामक पोस्टर, बैनर और नारे खुले आम लगाए गए थे। फ़रवरी 2026 में अमेरिका-इस्राईल के हवाई हमलों में अयातुल्ला ख़ामेनेई व उनके कई परिजन शहीद हो गए थे जिसके बाद हुए उनके विशाल अंतिम संस्कार में ईरानी लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजधानी तेहरान और ख़ामेनेई के दफ़्न वाले शहर मशहद की सड़कों पर जगह जगह अंग्रेज़ी में 'KILL TRUMP' लिखे बड़े-बड़े बैनर और धमकी भरे पोस्टर देखे गये। काले कपड़ों में शामिल महिलाओं और प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में KILL TRUMP लिखे हुए लाल रंग के प्लेकार्ड उठा रखे थे। कई पोस्टर्स में डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इस्राईली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों पर बंदूक की दूरबीन का निशाना क्रॉस हेयर बना हुआ था। उन पोस्टरों पर नीचे लिखा था- There will be blood यानी ख़ून बहेगा। इसी तरह तेहरान में एक पुल से ट्रंप का एक विशाल बिलबोर्ड (होर्डिंग) लटकाया गया था, जिस पर उनके सिर पर गोली का निशान बना था और लिखा था अमेरिका ने हमारे पिता को मारा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं! और वहां से गुज़रती आक्रोशित भीड़ उस होर्डिंग पर पत्थर बरसा रही थी। ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस में भी भीड़ ने सामूहिक रूप से क़सम खाते हुए नारे लगाए कि हम अपने सर्वोच्च नेता के ख़ून की क़सम खाते हैं, ट्रंप हम तुम्हें मार डालेंगे! मुख्य मंच से कवियों और उद्घोषकों ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हुए भीड़ से पूछा, दुनिया का सबसे कमीना आदमी (डोनाल्ड ट्रंप) अभी तक ज़िंदा क्यों है? जिसने हमारे इमाम को मारा, हम उसे क्यों न मारें? इसके बाद पूरी भीड़ ने डेथ टू डोनाल्ड के नारे लगाए। यहाँ तक कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा ख़ामेनेई ने भी लिखित बयान जारी कर कहा कि ईरान ने इन अपराधी हत्यारों की एक हिट-लिस्ट तैयार की है और उनसे बदला लेना अब ईरान का राष्ट्रीय संकल्प है। इसतरह के हालात ट्रंप व उनके सुरक्षा सलाहकारों में ईरान के प्रति भयभीत होने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कहना ग़लत नहीं होगा कि अपने ही ग़लत फैसलों के चलते ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं।

पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा छिड़ गई है।

माइक लेविन जैसे कई अमेरिकी सांसदों और मरीन सैनिकों के परिवारों ने भी यह खुलासा किया कि युद्धपोत पर जीवन नरक जैसा हो गया है। कई हफ़्तों तक जहाज़ पर गर्म पानी नहीं मिलता और टॉयलेट्स व शावर आदि ख़राब हो चुके हैं। लॉन्ड्री सुविधा बंद रहने से सैनिक गंदे कपड़े पहनने को मजबूर हैं। युद्धपोत पर भोजन और ज़रूरी सामानों की भारी कमी हो गई, यहाँ तक कि राशन कम होने पर सैनिकों को भोजन में बेहद कम व सीमित मात्रा दी जा रही है। और तो और युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से बहरीन जैसे अमेरिकी ठिकानों से जहाज तक रसद पहुँचाना भी मुश्किल हो गया है। इस हादसे,अमेरिकी सांसदों के दबाव और परिवारों के आक्रोश के बाद अब अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ ने घोषणा की है कि युद्धपोत को अब रोटेशन प्लान के तहत वापस बुलाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी जगह लेने के लिए दूसरे विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा जा रहा है ताकि थके हुए सैनिकों को राहत मिल सके। परन्तु इस ख़बर ने वर्तमान समय में अमेरिकी सैनिकों की उबावपूर्ण स्थिति तो उजागर कर ही दी है।

उधर ईरान की तरफ़ से संभावित ख़तरे के संदेह में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अंतिम समय में विमान बदलने से जुड़ी हुई एक हैरतअंगेज़ ख़बर सामने आई। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार पिछले महीने तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन से निकलते समय ट्रंप ने गुपचुप तरीक़े से अपना विमान बदल लिया था। ख़बरों के मुताबिक़ अमेरिकी राष्ट्रपति टेलीविज़न कैमरों की मौजूदगी में एयर फ़ोर्स वन में सवार हुए, फिर उन्हें चुपके से एक ऊंचे एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक में ले जाया गया और एक सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। हालांकि, अब वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने एक बार फिर विमान बदल दिया था। पोस्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप को पुराने एयर फ़ोर्स वन विमान से एक कैटरिंग कंटेनर में बाहर निकाला गया। यह कंटेनर ट्रंप को एक छोटे सी-32ए विमान तक ले गया। इसी विमान से उन्होंने ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी। इस दौरान विमान में सवार पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इससे पहले अंकारा में शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान का 'नंबर वन निशाना' हैं।

ट्रंप के ईरान से भयभीत होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जुलाई 2026 में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या से जुड़े बेहद आक्रामक पोस्टर, बैनर और नारे खुले आम लगाए गए थे। फ़रवरी 2026 में अमेरिका-इस्राईल के हवाई हमलों में अयातुल्ला ख़ामेनेई व उनके कई परिजन शहीद हो गए थे जिसके बाद हुए उनके विशाल अंतिम संस्कार में ईरानी लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजधानी तेहरान और ख़ामेनेई के दफ़्न वाले शहर मशहद की सड़कों पर जगह जगह अंग्रेज़ी में 'KILL TRUMP' लिखे बड़े-बड़े बैनर और धमकी भरे पोस्टर देखे गये। काले कपड़ों में शामिल महिलाओं और प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में KILL TRUMP लिखे हुए लाल रंग के प्लेकार्ड उठा रखे थे। कई पोस्टर्स में डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इस्राईली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों पर बंदूक की दूरबीन का निशाना क्रॉस हेयर बना हुआ था। उन पोस्टरों पर नीचे लिखा था- There will be blood यानी ख़ून बहेगा। इसी तरह तेहरान में एक पुल से ट्रंप का एक विशाल बिलबोर्ड (होर्डिंग) लटकाया गया था, जिस पर उनके सिर पर गोली का निशान बना था और लिखा था अमेरिका ने हमारे पिता को मारा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं! और वहां से गुज़रती आक्रोशित भीड़ उस होर्डिंग पर पत्थर बरसा रही थी। ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस में भी भीड़ ने सामूहिक रूप से क़सम खाते हुए नारे लगाए कि हम अपने सर्वोच्च नेता के ख़ून की क़सम खाते हैं, ट्रंप हम तुम्हें मार डालेंगे! मुख्य मंच से कवियों और उद्घोषकों ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हुए भीड़ से पूछा, दुनिया का सबसे कमीना आदमी (डोनाल्ड ट्रंप) अभी तक ज़िंदा क्यों है? जिसने हमारे इमाम को मारा, हम उसे क्यों न मारें? इसके बाद पूरी भीड़ ने डेथ टू डोनाल्ड के नारे लगाए। यहाँ तक कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा ख़ामेनेई ने भी लिखित बयान जारी कर कहा कि ईरान ने इन अपराधी हत्यारों की एक हिट-लिस्ट तैयार की है और उनसे बदला लेना अब ईरान का राष्ट्रीय संकल्प है। इसतरह के हालात ट्रंप व उनके सुरक्षा सलाहकारों में ईरान के प्रति भयभीत होने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कहना ग़लत नहीं होगा कि अपने ही ग़लत फैसलों के चलते ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं।

राजनीति

अनिल ठाकुर

तीन नए प्रयोग और बदलती राजनीतिक जमीन

वर्ष 2026 में भारतीय राजनीति में तीन ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जो पारंपरिक राजनीति की स्थापित धारणाओं से कुछ अलग दिखाई देते हैं। तीनों घटनाओं की प्रकृति और राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें एक समानता स्पष्ट है–जनता के एक हिस्से में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष और नए विकल्प की तलाश।

थलपथी विजय: तमिल राजनीति में नई चुनौती

अप्रैल 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नवगठित टीवीके के नेता थलपथी जोसेफ विजय की पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल कर द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसी स्थापित पार्टियों के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी किसी नई पार्टी की ऐसी सफलता स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करती है।

विजय की विचारधारा का बड़ा हिस्सा तमिल राजनीति की उसी सामाजिक-राजनीतिक जमीन से जुड़ा दिखाई देता है, जिस पर द्रमुक और अन्य द्रविड़ दल लंबे समय से खड़े हैं। फिर उनकी सफलता का कारण क्या है?

तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्यों में फिल्मी सितारों के प्रति जनता का आकर्षण राजनीति में पहले भी दिखाई देता रहा है। अन्नादुरई और करुणानिधि से लेकर एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता तक, सिनेमा से राजनीति में आए नेताओं ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक शक्ति में बदला है। आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव इसका बड़ा उदाहरण हैं। थलपथी विजय उसी परंपरा की नई कड़ी हैं।

लेकिन केवल फिल्मी लोकप्रियता से चुनावी सफलता की व्याख्या करना पर्याप्त नहीं होगा। संभवतः स्थापित राजनीतिक दलों से एकरूपता की थकान, युवा मतदाताओं में नए चेहरे की तलाश और विजय का स्वयं को उनकी आवाज के रूप में प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।

हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि विजय का करिश्मा कितने समय तक कायम रहेगा। इसका बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि द्रमुक अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमियों को कितनी जल्दी पहचानकर सुधारती है। तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वह सत्ता की सीधी दावेदार दिखाई दे; उसे अभी अपने आधार को मजबूत करने की चुनौती से गुजरना है।

प्रशांत किशोर : रणनीतिकार से राजनीतिक नेता तक

दूसरा महत्वपूर्ण नाम जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर का है। वे राजनीति में नए जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में नहीं। 2014 से चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान किसी भी प्रादेशिक नेता से कम नहीं रही है।

जनसुराज के औपचारिक गठन से पहले ही उन्होंने बिहार को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया और पिछले तीन वर्षों में लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की। विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन परिणाम बेहद निराशाजनक रहे और अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके।

इसके महज आठ महीने बाद बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने और भाजपा की प्रतिष्ठित सीट पर सफलता हासिल करने से निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा तेज हुई। स्वाभाविक रूप से इस परिणाम के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं और इसे 2029 के संभावित राजनीतिक बदलाव का संकेत भी बताया जा रहा है।

लेकिन इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। बांकीपुर के चुनाव के समय भाजपा के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल नहीं थीं। छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार की छवि प्रभावित हुई, भाजपा के भीतर की उठापटक के कारण उम्मीदवार बदलना पड़ा, सवर्ण मतदाताओं में असंतोष था और राजद की निष्क्रियता ने भी चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले के बजाय अलग दिशा दे दी। इन सभी परिस्थितियों का सम्मिलित प्रभाव परिणाम पर पड़ा।

इसलिए बांकीपुर की जीत को तत्काल किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का निर्णायक संकेत मानना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन पीके को हल्के में लेना भी उतनी ही बड़ी भूल होगी।

2029 में उनकी असली परीक्षा यह होगी कि वे राजद की पिछड़ा-दलित राजनीति के सामने अपना अलग सामाजिक और राजनीतिक आधार कैसे तैयार करते हैं। फिलहाल उनके सामने पहला लक्ष्य राजद के प्रभाव को चुनौती देने योग्य संगठन खड़ा करना होना चाहिए।

बांकीपुर का संदेश फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार का युवा मतदाता स्थापित राजनीतिक विकल्पों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और भाजपा के लिए भी यह एक चेतावनी है।

अभिजीत दीपके: आंदोलन से राजनीतिक विकल्प तक?

तीसरा नाम अभिजीत दीपके का है। एक छोटी-सी टिप्पणी को आधार बनाकर जिस तरह उन्होंने व्यापक आंदोलन खड़ा किया, वह भारतीय राजनीति में कम देखने को मिलता है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी राजनीतिक सफलता को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है।

हालांकि आंदोलन के शुरुआती लगभग 15 दिनों तक जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक रूप से सक्रिय आंदोलनकारियों के बजाय तमाशबीनों जैसा दिखाई देता था। जब 15 दिन बाद केजरीवाल मंच पर आए, तब आंदोलन का चरित्र तेजी से राजनीतिक होता गया।

इसी दौरान सरकार द्वारा वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई भी राजनीतिक दृष्टि से बड़ी भूल साबित हुई। यदि उसी समय आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनके प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति बना दी जाती और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया जाता, तो संभवतः आंदोलन को इतना विस्तार नहीं मिलता।

अब यदि सीजेआई की ओर से सीधे मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो इससे आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप को लेकर संदेह की गुंजाइश काफी कम रह जाती है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मामला केवल मूल मांगों तक सीमित नहीं रह गया है।

अब भाजपा को किसी गैर-राजनीतिक आंदोलन से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संगठन से मुकाबला करना होगा। इंडी गठबंधन में 28 के बजाय 29 दलों की संख्या बढ़ जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं है। असली प्रश्न यह है कि दीपके और उनकी पार्टी चुनावी राजनीति में अपने लिए कितनी स्वतंत्र जगह बना पाती है।

सीजेआई यदि जंतर-मंतर पार्ट-2 की तैयारी कर रही है तो सरकार को इस बार पिछली गलतियों से सीखना होगा। किसी भी गैर-राजनीतिक मंच से शुरू होने वाले आंदोलन को प्रारंभिक अवस्था में ही गंभीरता से समझना और उसकी वास्तविक मांगों पर बातचीत करना राजनीतिक रूप से अधिक समझदारी होगी।

तीनों प्रयोगों का भविष्य

इन तीनों घटनाक्रमों को एक साथ देखने पर भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। थलपति विजय के सामने लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक संगठन में बदलने की चुनौती है। प्रशांत किशोर के सामने रणनीतिकार की पहचान से आगे निकलकर एक मजबूत सामाजिक-राजनीतिक आधार बनाने की चुनौती है। वहीं अभिजीत दीपके के सामने आंदोलन की ऊर्जा को स्थायी राजनीतिक विकल्प में बदलने की चुनौती है।

मेरे आकलन में थलपति विजय और प्रशांत किशोर के पास भारतीय राजनीति में लंबे समय तक अपनी जगह बनाने की संभावनाएँ अधिक दिखाई देती हैं। दीपके और उनकी पार्टी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे किसी एक मुद्दे या आंदोलन से आगे निकलकर अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार कैसे बनाते हैं।

आज जिन वामपंथी बुद्धिजीवियों और विचारकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, संभव है कि चुनावी राजनीति में उनका एक बड़ा हिस्सा अंततः कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दे। तब असली परीक्षा होगी कि दीपके की राजनीति अपने दम पर कितनी दूर तक जाती है।

अंततः 2026 के ये तीनों घटनाक्रम किसी अंतिम राजनीतिक परिवर्तन की घोषणा नहीं करते, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि भारतीय मतदाता–विशेषकर युवा मतदाता–स्थापित राजनीतिक विकल्पों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। नए चेहरे, नए प्रयोग और नए राजनीतिक आख्यान के लिए जगह बन रही है।

2029 तक इनमें से कौन उस जगह को स्थायी राजनीतिक शक्ति में बदल पाता है, भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में यह सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

अरुण अर्णव खरे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमारे शहर में भी आया सावन झूम के

सारे देश की देखादेखी हमारे शहर में भी सावन आ गया है। अब सावन आया है तो वह झूम के बरसेगा या झूम के नहीं बरसेगा। सावन झूम के बरसा तो परेशानी और न बरसा तो परेशानी। इधर सावन झूम के बरसा, सड़कों ने भीगना शुरु किया और उधर सिस्टम नंगा होने लगा। व्यवस्था की पोल खुलने लगी। सड़कें जो पहले से थोड़ी-बहुत टूटी हुई थी, खुल कर टूटने लगीं। उन्हें सड़क कहलाने में शर्म आने लगी। उन पर चलने से लोग डरने लगे। पता नहीं कब चलते-चलते गड्ढा आ जाए और वे उसमें समा जाएँ। राजमार्गों की डिग्निटी भी खतरे में है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए जाने के भ्रम में वे कहीं के नहीं रहे। कहीं-कहीं तो गाँव की सड़कों से भी बदतर हो गए।

नाला जिसे ढँका गया था, सारी अड़चनों को धता बताते हुए सम्मान सहित ऊपर आ गया। पूरा जोर लगाकर उफनाने लगा। जहाँ नाले का अस्तित्व ही न था, वहाँ भी वह प्रकट हो गया। नगर निगम का बयान आया 'नालों की सफाई समय पर की गई थी, लेकिन सावन किसी शराबी की तरह बहुत झूम के आ गया।' ऐसे बहाने हमारे शहर में प्राइमरी स्कूल के बच्चे बनाते हैं - 'हमने पढ़ाई बहुत की थी, पर पेपर बाहर से आ गया'।

पुलों की जान साँसत में है। सावन में उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी हमेशा से डराता आया है। पिछले सावन में कई पुल धड़ाधड़ गिरे थे। इस साल भी सावन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। सावन की आहट पाते ही गुजरात का गंभीरा पुल खुद तो गिरा ही, गुजरने वाले वाहनों को भी ले डूबा। नैतिक मूल्यों और आचरण से गिरने-गिराने के इस दौर में पुल को भी गिरने का लोकतांत्रिक अधिकार है, वे गिरें, जरूर गिरें, नए-नवेले गिरें, जर्जर होकर गिरें, लेकिन बेबस लोगों को साथ न ले जाएँ, बस हमारी इतनी इल्तिजा है।

पहाड़ दुखी हैं। बेचारे जबरिया विकास के मारे हैं। हर सावन उनसे कुछ न कुछ छीन कर ले जाता है। वे पुल नहीं हैं इसलिए पुल सरीखे नहीं गिरते, वे प्राकृतिक हैं, केवल धसकते हैं। उनकी प्रकृति से छेड़छाड़ उन्हें धसकने को विवश करती है। वे जब धसकते हैं, तो जो भी सामने मिल जाता है, उसे समेटते चलते हैं। व्यवस्था इसे आपदा बताती है। प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इसे बताने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। अगले साल इसी स्क्रिप्ट को दोहराना जो है, शायद इसलिए।

नायिका भी पीड़ा में है। उसका दुख सबसे अलग है। वह सावन को अमूल्य समझती है। बारिश में भीगते हुए वह प्रीतम को उलाहना देते हुए गाती फिरती है - 'तेरी दो टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए।' कभी-कभी रात में उसके घर से यह आवाज आती सुनी जाती है - 'मेरे नयना सावन-भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा।' उसके दुख में पपीहा भी शामिल है लेकिन पति को चिंता नहीं है। वह वोटरलिस्ट सुधारने में लगा हुआ है। मुर्दा लोग उसे ठीक से काम नहीं करने दे रहे, रोज-रोज चले आते हैं जिंदा होने का सबूत लेकर। पशोपेश में है वह, दोबारा उन्हें जिंदा बना दे तो नौकरी पर खतरा और मरा ही रहने दे, तो भी नौकरी पर खतरा और जिल्लत साथ में। अब वह नौकरी बचाए या सावन के गीत गाए..

हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सावन के झूम के बरसने से केवल परेशानी ही परेशानी हो, ऐसा कदापि नहीं है। किसान, सरकार, नदी, सरोवर, रील बनाने वाले, कवि और हाशिए पर पड़े कुछ रिटायर्ड अफसर बहुत खुश हैं। किसान के ऊपर देश का पेट पालने का जिम्मा है इसलिए बेचारे की मजबूरी है कि अपने चुंचवाते छप्पर की अनदेखी कर खुश होने की। सरकार भविष्य में अपना खजाना भरने की कल्पना करके खुश है। नदी को अपनी अल्हड़ता वापस मिलने की खुशी है तो तलछट्ट देखकर दुबले हो चुके सरोवर को फिर से जवान हो जाने की खुशी है। रील बनाने वाले तो हर मौसम में खुश रहते हैं। गर्मियों में सूरज के साथ सेल्फी लेने वालों को बरसते पानी में मोर सा नाचते हुए और उफनती नदी की धाराओं से अठखेलियाँ करते हुए शूटिंग करने का मौका मिल रहा है। यह अलग बात है कि उनमें से कुछ इस चक्कर में अपना जीवन-चक्र पूरा कर बैठे। रिटायर्ड अफसर व्यक्तिगत कारणों से खुश हैं। उन्हें लगता है कि तमाम तरह के परहेजों, ग्लाइकोफेज और टेल्मा गोलियों, कायम चूर्ण तथा वालिनी स्प्रे के चंगुल में फँसी जिंदगी में दो चार दिन सुकून के आएँगे और उन्हें भी दूसरों की तरह बिना रोकटोक बालकनी में बैठकर भजिया खाने का आनंद मिल सकेगा।कवि भी खुश है, हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से खुश होने की कोई मजबूरी नहीं है लेकिन वह खुश है केवल 'जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि' कहावत को सही सिद्ध करने के लिए। जब सावन झूम के बरसता है तो रवि कहीं नहीं पहुँचता, लेकिन कवि है कि वहाँ पर पहुँच ही जाता है, नायिका के दुख से बेपरवाह, चटखारे लेते हुए 'बरखा रानी जरा जम के बरसो' ताकि 'सुलग सुलग जाए मन' का रोमांचकारी दृश्य देख सके।

उपलब्धि

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

मप्र से 'पेबल बीच' तक पहुँचा भारत का गौरव

मानवेन्द्र सिंह की स्कूली शिक्षा इंदौर के डेली कॉलेज में हुई,उसके बाद उन्होने जिम रसेल इंटरनेशनल रेसिंग ड्राइवर्स स्कूल, कनाडा से फॉर्मूला फोर्ड रेसिंग में स्नातक, क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर से बी.ए., नॉर्थवुड विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. से ऑटो मार्केटिंग डिग्री, मैकफर्सन कॉलेज, यू.एस.ए. इंटर-टर्म ऑटो रेस्टोरेशन, में नॉर्थवुड विश्वविद्यालय के 'उत्कृष्ट पूर्व छात्र से पुरस्कृत रहे। मानवेंद्र सिंह ने भारत की पहली विंटेज और क्लासिक कार रिस्टोरेशन वर्कशॉप 'क्लासिक कार' इंदौर की शुरुआत 1978 में की जो आज भी क्रियाशील है। उनके द्वारा सेकड़ों विंटेज कारों का रिस्टोरेशन किया गया है। वे भारत में विंटेज और क्लासिक कारों के एक विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित हैं। इसके लिए उन्होंने दूरदर्शन, बीबीसी, सीएनबीसी, सहारा, स्टार टीवी और यहां तक कि एमटीवी पर कई टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने 1979 में नई दिल्ली के अशोका होटल में भारत का पहला कस्टम कार शो आयोजित किया था।

दुनिया में यदि क्लासिक और विंटेज कारों का कोई सबसे प्रतिष्ठित मंच है, तो वह है अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में आयोजित 'पेबल बीच कॉनकोर्स डी'एलिगेंस'। यहाँ केवल दुर्लभ और ऐतिहासिक कारों का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ उनकी मौलिकता, इतिहास, डिज़ाइन और संरक्षण का मूल्यांकन करते हैं इस प्रतियोगिता को दुनिया में कारों का आस्कर कहा जाता है,यह आयोजन हर बरस अगस्त माह मे आयोजित किया जाता है।

ऐसे प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व हैं-मानवेन्द्र सिंह बड़वानी। यह उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल विरासत को मिली वैश्विक मान्यता का प्रतीक है।

निमाड़ से विश्व मंच तक- मध्य प्रदेश के तत्कालीन बड़वानी राजघराने के वर्तमान प्रमुख मानवेन्द्र सिंह का बचपन ऐसी विरासत के बीच बीता, जहाँ शाही मोटरकारें केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत दस्तावेज़ थीं,ओर यही जुनून उन्हे विश्व मंच तक ले गया।

मानवेन्द्र सिंह की स्कूली शिक्षा इंदौर के डेली कॉलेज में हुई,उसके बाद उन्होंने जिम रसेल इंटरनेशनल रेसिंग ड्राइवर्स स्कूल, कनाडा से फॉर्मूला फोर्ड रेसिंग में स्नातक, क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर से बी.ए., नॉर्थवुड विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. से ऑटो मार्केटिंग डिग्री, मैकफर्सन कॉलेज, यू.एस.ए. इंटर-टर्म ऑटो रेस्टोरेशन, में नॉर्थवुड विश्वविद्यालय के 'उत्कृष्ट पूर्व छात्र से पुरस्कृत रहे।

मानवेंद्र सिंह ने भारत की पहली विंटेज और क्लासिक कार रिस्टोरेशन वर्कशॉप 'क्लासिक कार' इंदौर की शुरुआत 1978 में की जो आज भी क्रियाशील है। उनके द्वारा सेकड़ों विंटेज कारों का रिस्टोरेशन किया गया है। वे भारत में विंटेज और क्लासिक कारों के एक विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित हैं। इसके लिए उन्होंने दूरदर्शन, बीबीसी, सीएनबीसी, सहारा, स्टार टीवी और यहां तक कि एमटीवी पर कई टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने 1979 में नई दिल्ली के अशोका होटल में भारत का पहला कस्टम कार शो आयोजित किया था।

समय के साथ उनका यह शौक गहन अध्ययन और शोध में बदल गया। उन्होंने भारत की रियासतों में संरक्षित दुर्लभ कारों का दस्तावेज़ीकरण किया, उनके इतिहास का अध्ययन किया और उन्हें संरक्षित रखने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई, भारत में मोटर कारों ओर राजा महाराजाओं के इतिहास पर उन्होंने सह-लेखन में भारत के ऑटोमोटिव इतिहास पर पहली पुस्तक 'ऑटोमोबाइल्स ऑफ द महाराजा' को जारी किया। पुस्तक में भारत में मोटर चालित परिवहन को अपनाने में महाराजाओं के प्रभाव को शामिल किया गया है। यह शासकों के विशाल संग्रह का विवरण है। पुस्तक के लिए सामग्री

विशाल व्यक्तिगत पुस्तकालय और खुद मानवेंद्र सिंह के दशकों के विस्तृत शोध से है। वह एक निजी ऑटोमोटिव लाइब्रेरी का रखरखाव करते हैं जिसमें शुरुआती युग से लेकर वर्तमान तक की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो पत्रिकाएं, ब्रोशर/कैटलॉग, विज्ञापन, पुस्तकें और मूल तस्वीरें शामिल है। मानवेंद्र सिंह एक संग्रहकर्ता से कहीं अधिक है, दुनिया में अनेक लोग विंटेज कारें खरीदते हैं, लेकिन मानवेन्द्र सिंह का योगदान इससे कहीं बड़ा है। वे कारों के इतिहास, उनकी तकनीकी विशेषताओं, मूल स्वरूप और सांस्कृतिक महत्व के विशेषज्ञ हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक ऐतिहासिक कार अपने समय की कला, विज्ञान और समाज का दर्पण होती है। इसलिए उसका संरक्षण मानव इतिहास के संरक्षण जैसा ही महत्वपूर्ण है।

पेबल बीच में भारतीय पहचान

इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1950 में हुई। प्रारम्भ में इसका उद्देश्य सुंदर और दुर्लभ मोटरकारों का प्रदर्शन था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह आयोजन अपने कठोर मानकों, निष्पक्ष मूल्यांकन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण विश्व की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता बन गई, और इसे देखने हजारों दर्शक, संग्राहक, इतिहासकार और विशेषज्ञ पहुँचते हैं। आज किसी कार का पेबल बीच में चयन होना ही अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता है।

'पेबल बीच कॉनकोर्स डी'एलिगेंस' में निर्णायक बनने के लिए दशकों का अनुभव, गहरा शोध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आवश्यक होती है। मानवेन्द्र सिंह ने वर्षों तक विभिन्न श्रेणियों की दुर्लभ कारों का मूल्यांकन किया। उनकी विशेषज्ञता के कारण उन्हें विश्वभर के संग्राहकों और आयोजकों का सम्मान प्राप्त हुआ, इन्ही के चलते सन् 2012 से वे पेबल बीच के निर्णायक मण्डल (जज-जूरी) में शामिल है,उन्हें 2018 में पेबल बीच का प्रतिष्ठित 'लोरिन ट्रायन ट्रॉफी ' अवार्ड प्रदान किया गया, यह ट्रॉफी उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने विंटेज कारों के संरक्षण में काम किया है, यह ट्रॉफी लोरीन ट्रायन की याद में प्रदान की जाती है, जो इस आयोजन के सह-अध्यक्ष रहे थे।

मानवेंद्र सिंह ने विशेष रूप से भारतीय राजघरानों की कारों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके प्रयासों से दुनिया को यह समझ आया कि भारत में भी विश्वस्तरीय ऑटोमोबाइल विरासत सुरक्षित रही है।

वक्रोक्ति

अतुल चतुर्वेदी

लेखक साहित्यकार हैं।

चार देश भक्ति गीतों तक क्यों सिमटा आज़ादी का अर्थ

मशहूर शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की प्रसिद्ध नज़्म - बोल की लब आज़ाद हैं तेरे लिखी के उनवान को हमारे नागरिकों ने ईमानदारी से पकड़ लिया है कसकर । उसके लब आज़ाद हैं वो कुछ भी कह सकता है ...सरकार की कमियाँ बता सकता है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकता है, स्वयं वही आचरण करते हुए दूसरों को भला बुरा कह सकता है, घूस लेते हुए भ्रष्टाचार पर भाषण पेल सकता है, सनातन की बात करते हुए दारू की पूरी बोतल गटक सकता है, हिंदी पखवाड़े पर लेख लिखते हुए अपने बच्चे कान्वेंट में पढ़वा सकता है । चूँकि यह कहा गया है कि लब आज़ाद हैं तेरे तो वो अपनी अभिव्यक्ति को लेकर मुखर है। व्यवस्था को इल्हाम है कि हमारे नागरिक कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं लिहाजा इस मुखरता को कसने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं ।

आज़ादी को लेकर हमारा फलसफ़ा बहुत स्पष्ट है हम मानते हैं कि देश आज़ाद है तो हर नागरिक भी अपनी स्वेच्छाचारिता को आज़ाद है। कहीं भी गाड़ी खड़ी करो, कहीं भी अतिक्रमण करो और किसी को भी गरियाओ। आज़ादी का इससे बड़ा सुकून और क्या होगा कि आप हर समय सरकार को हर कमी के लिए कोस सकते हैं और अपनी मूर्खताओं को मुस्तैदी से ढाँक सकते हैं। एक स्वतंत्र देश के नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो सरकार और व्यवस्था से सवाल जवाब करे लेकिन जब स्वयं का मुद्दा आए तो या तो समाज, जाति की तख्ती लगाकर छुप जाये या जुगाड़ के बिल में गड्ढे खोद वहाँ मुँह छुपाए पड़ा रहे।

मशहूर शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की प्रसिद्ध नज़्म - बोल की लब आज़ाद हैं तेरे लिखी के उनवान को हमारे नागरिकों ने ईमानदारी से पकड़ लिया है कसकर। उसके लब आज़ाद हैं वो कुछ भी कह सकता है ...सरकार की कमियाँ बता सकता है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकता है, स्वयं वही आचरण करते हुए दूसरों को भला बुरा कह सकता है, घूस लेते हुए भ्रष्टाचार पर भाषण पेल सकता है, सनातन की बात करते हुए दारू की पूरी बोतल गटक सकता है, हिंदी पखवाड़े पर लेख लिखते हुए अपने बच्चे कान्वेंट में पढ़वा सकता है। चूँकि यह कहा गया है कि लब आज़ाद हैं तेरे तो वो अपनी अभिव्यक्ति को लेकर मुखर है। व्यवस्था को इल्हाम है कि हमारे नागरिक कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं लिहाजा इस मुखरता को कसने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं।

अब लबों की आज़ादी ख़तरे में हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गहन चिंतन मनन चालू है, प्रयास भी हो रहे हैं। छुटपुट बमबारी भी जारी है।

आज़ादी के हमारे लिए सच्चे मायने यह हैं कि हमारी अनुशासनहीनता को लेकर कोई रोके टोके नहीं, हमारी अराजकता को स्वीकार कर लिया जाये । एक आम नागरिक बस इसे ही आज़ादी मानता है। बाद में वो अंततः जाति, समाज, कुनबे, गोत्र , अल्ल के सींखचे में खुशी खुशी क़ैद हो जाता है। उसके चिंतन की उड़ान मात्र स्वयं की सुविधाओं के आकाश तक की है। यही है उसका स्वप्न और यही उसकी अधिकतम महत्वाकांक्षा।

धार्मिक पर्वों पर हम जोर जोर से स्पीकर लगा कर पूरे मोहल्ले और आवागमन को प्रभावित कर सकें। पर्यावरण प्रेम के नाम पर स्टीप लैंड पर वृक्षारोपण कर अपने प्रकृति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। रेड लाइट हो और ट्रैफिक सिपाही न हो तो गाड़ी निकाल सकें, सरकारी स्कूलों में दादागिरी चला सकें, अस्पताल में चिकित्सकों की गिरेबान पकड़ सकें, किसी के भी निजी जीवन में ताँक झाँक कर सकें तो बस यहीं हमारी आज़ादी की भावना का पवित्र उफान

संतुष्ट हो जाता है। इस देश को रखना बच्चों सँभाल के ...इस सदाबहार गीत से हमारी मुक्ति हो जाती है। सँभाल के तुम रखना अब, हमने तो जो चौपट करना था कर दिया अपनी करतूतों से ...तुम संभाल के रखना। अब तुम से ही उम्मीद है। उम्मीदों का बोझ तुम्हारे काँधे पर डालकर...इस दुनिया को और मैला, हिंसक, क्रूर, अमानवीय, प्रदूषित कर हम तो जा रहें हैं ...बच्चों! तुम संभाल कर रखना । सब आशाएँ हमारी नई पीढ़ी से होती हैं। वो हमारा रुदन बॉक्स हैं। हमारे जमाने में तो ...इस वाक्य से शुरू हुआ प्रलाप कभी ख़त्म नहीं होता। आज़ादी का उत्सव चार देश भक्ति गीतों के सहारे राजीखुशी संपन्न हो जाता है।

ऐसे ही एक और देश भक्ति का शाश्वत गीत है - ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी ...जब नेताओं के मुँह में सत्ता सुख और वैभव को देख पानी आ जाए और वे संवेदनहीन हो जातें तो जनता की आँखों में से तो पानी आयेगा ही। जब बढ़ते करों और सर्विस टैक्स की मार से, उद्योगपतियों के एन पी एस से बैंक कंगाली में हो तो वतन के लोग आँख में पानी ही भरेंगे। लोकतंत्र में एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद जनता पानी ही भरती है पाँच साल तक। और कुशल राजनेता बयानों के हंटर लगा लगा कर पानी भरवाता है। परंतु इससे क्या है आज़ादी का उत्सव तो चार देश भक्ति गीतों और पाँच सात गुब्बारों और सफ़ेद कबूतरों के बलबूते धूमधाम से निबट जाता है।

ज़ेन जी को कोसने से नहीं उनके संघर्षों को मनोबल को दिशा देने से, उनकी पीड़ाओं को समाधान देने से हल निकलेगा फ्रेंड्स! काश! सोच और व्यवहार की एकरूपता के इस स्तर पर हम व्यवहार कर पायें तो आज़ादी के सही मायने हमको समझ में आ जाएँगे। न तो किसी को गरियाना आज़ादी है, न किसी को बेवजह कोसना आज़ादी।

आज़ादी वो है जो दूसरों की स्वतन्त्रता और अस्तित्व का भी उतना सम्मान करे जितना स्पेस हम अपने लिए पसंद करते हैं। एक खुली हवा में साँस तब ही ली जा सकती है जब आपने उम्मीद, खुलेपन और विमर्श के पेड़ दूसरों के लिए भी लगाये हों, संभावनाओं की ऊर्वर भूमि आने वाली संततियों के लिए भी तैयार की हो।

विरासत

सविता आनंद

(संस्थापक, विरासत-ए-बिस्मिल्लाह एवं विरासतनामा; सांस्कृतिक विरासत और संगीत परंपराओं के दस्तावेज़ीकरण पर कार्यरत)

बिस्मिल्लाह और मैं : एक सफ़र, एक याद...

कुछ मुलाक़ातें चंद लम्हों की होती हैं, लेकिन उनका असर उम्र भर साथ चलता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ साहब से मेरी पहली मुलाक़ात भी ऐसी ही थी।

'बिस्मिल्लाह मेरे लिए केवल एक याद नहीं, एक रास्ता हैं–वह रास्ता जो 2006 में शुरू हुआ और आज भी जारी है। क्योंकि कुछ रिश्तों की कोई पुण्यतिथि नहीं होती; वे याद से विरासत बन जाते हैं।'

वर्ष 2006 में दिल्ली में एक कार्यक्रम के सिलसिले में उनसे मुलाक़ात हुई। सामने वह शख़्स था, जिसकी शहनाई की गूँज दुनिया भर में सुनाई दे रही थी, लेकिन बातचीत में न किसी बड़े फ़नकार का रौब था, न शोहरत का कोई बोझ। बस बनारस की वही सहजता, सादगी और मिठास थी, जो उन्हें अपने समकालीन कलाकारों से अलग पहचान देती थी।

न जाने किस मासूमियत में मैंने उनसे पूछ लिया, 'क्या आप मुझे शहनाई बजाना सिखा देंगे?'

उस्ताद मुस्कुराए और बोले 'बेटी, क्या तुम बजा पाओगी? इसमें बहुत जान लगती है, फेफड़ों से फूँक डालनी पड़ती है। ' उस वक़्त मेरे पास शायद इसका कोई जवाब नहीं था। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है, मैं उनसे शहनाई तो नहीं सीख पाई, मगर विरासत का मतलब ज़रूर सीख गई। उसी वर्ष उस्ताद इस दुनिया से रुख़सत हो गए। लेकिन मेरे लिए वह छोटी-सी मुलाक़ात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अजीब बात है कि किसी शख़्स के चले जाने के बाद उससे रिश्ता अक्सर स्मृति बन जाता है, मगर मेरे मामले में वह स्मृति धीरे-धीरे एक सफ़र में बदलती गई।

2011 में पहली बार बनारस जाना हुआ। उस्ताद के परिवार से मुलाकात का वह रिश्ता केवल उनकी याद तक सीमित नहीं रहा। उनके संगीत, उनके परिवार और उस सांस्कृतिक धरोहर को समझने की इच्छा बढ़ती गई जिसने बिस्मिल्लाह ख़ाँ को वह बनाया जिसे आज दुनिया जानती है। उसके बाद से उस्ताद के जीवन और करीब से जानने का अवसर मिलता रहा।

यादों से विरासत तक

वर्ष 2018 इस सफ़र का एक बेहद ख़ास पड़ाव बनकर आया, जब गूगल की टीम ने मुझसे संपर्क कर बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ की स्मृति में गूगल-डूडल दुनिया भर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मेरे लिए वह केवल एक डिजिटल श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि वर्षों से दिल में सँजोई उनकी स्मृति का वैश्विक सम्मान था - एक ऐसा क्षण, जो किसी पुरस्कार से कम नहीं लगा। तभी मन में एक सवाल ने जगह बनाई, क्या किसी महान फ़नकार को उसकी जयंती और पुण्यतिथि पर याद कर लेना ही काफ़ी है? या हमारी असल ज़िम्मेदारी यह भी है कि उसकी कहानी उस नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिसने उसे कभी देखा-सुना ही नहीं?

विरासत किसी संदूक में रखी पुरानी निशानी नहीं है। वह तभी ज़िंदा रहती है जब एक पीढ़ी उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाती है। माध्यम बदल सकते हैं कभी किताब, कभी रेडियो, कभी दूरदर्शन और आज मोबाइल की स्क्रीन लेकिन स्मृति की डोर नहीं टूटनी चाहिए। इसी सोच को 2021 में एक और शक्ल मिली - 'विरासत-ए-बिस्मिल्लाह' के रूप में। उस्ताद की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर लाइव प्रसारित हुआ। मेरे लिए वह महज़ एक

आयोजन नहीं था। वह 2006 में शुरू हुए एक सफ़र का अगला पड़ाव था। साथ ही उसने मेरे भीतर एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। बिस्मिल्लाह ख़ाँ तो एक नाम हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे कितने फ़नकार, कितने घराने, कितनी रवायतें और कितनी अनकही दास्तानें हैं जो धीरे-धीरे वक्त की गर्द में खोती जा रही हैं? कई कलाकार अपने भीतर सदियों की परंपरा लेकर हमारे बीच मौजूद हैं, मगर उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही। कई किस्से किताबों में नहीं, बुजुर्ग फ़नकारों की यादों में ज़िंदा हैं। कई घराने नई पीढ़ी के लिए सिर्फ़ नाम बनते जा रहे हैं। और शायद यहीं से विरासतनामा की सोच ने जन्म लिया। कहानियाँ जो दर्ज होनी चाहिए।

विरासतनामा मेरे लिए केवल एक डिजिटल माध्यम शुरू करने का विचार नहीं था। वह उसी बेचैनी का विस्तार था, जो बिस्मिल्लाह ख़ाँ की विरासत के साथ काम करते हुए मेरे भीतर पैदा हुई थी। एक कोशिश कि फ़नकारों की आवाज़ें दर्ज हों। घरानों की कहानियाँ सामने आएँ। संगीत और संस्कृति को केवल तारीख़ों और पुरस्कारों के सहारे न समझा जाए, बल्कि उन इंसानों के ज़रिए जाना जाए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी सुर, किसी वाद्य या किसी परंपरा को साधने में लगा दी।

आज हमारे सामने चुनौती केवल विरासत को बचाने की नहीं, उसे नई नस्ल की भाषा में सुनाने की भी है। अगर युवा पुराने अभिलेखागार तक नहीं पहुँच रहा, तो हमें अभिलेखागार उसके मोबाइल तक पहुँचाना होगा। अगर किसी राग, घराने या कलाकार की कहानी उसे कठिन लगती है, तो हमें उस कहानी को कमतर नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से कहना होगा। यही शायद उस्ताद से मिली सबसे बड़ी सीख भी है अपनी जड़ों में रहते हुए दुनिया तक पहुँचना।

बिस्मिल्लाह ख़ाँ ने शहनाई को किसी एक मज़हब, एक शहर या एक रस्म तक सीमित नहीं रहने दिया। उनके सुर में बनारस था, गंगा थी, मंदिर की सुबह थी और उस हिंदुस्तान की मिली-जुली तहज़ीब थी जिसकी पहचान उसके साझा सांस्कृतिक जीवन से बनती है। मेरे हिस्से के बिस्मिल्लाहः उस्ताद को इस दुनिया से गए बीस वर्ष हो चुके हैं।दुनिया उन्हें भारत रत्न, शहनाई के महान साधक और भारतीय संगीत के प्रतीक के रूप में याद करती है। मेरे हिस्से के बिस्मिल्लाह थोड़े अलग हैं। वे 2006 की वह मुस्कुराहट हैं।

वह सवाल 'बेटी, क्या तुम बजा पाओगी?'

2018 की एक स्क्रीन पर उभरी उनकी तस्वीर हैं।

2021 के 'विरासत-ए-बिस्मिल्लाह' में गूँजती शहनाई हैं।

और आज विरासतनामा के पीछे मौजूद वह एहसास हैं कि विरासत को सिर्फ़ याद नहीं किया जाता, उसे सँभाला भी जाता है। आज जब किसी फ़नकार की कहानी दर्ज करती हूँ, किसी भूली हुई रवायत के पीछे जाती हूँ या किसी नई पीढ़ी को हमारी सांगीतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो कहीं न कहीं 2006 की वह मुलाक़ात फिर सामने आ खड़ी होती है। तब मुझे मालूम नहीं था कि वह चंद मिनटों की मुलाक़ात मुझे कहाँ तक ले जाएगी। आज भी नहीं जानती कि यह सफ़र कहाँ तक जाएगा।

इतना जरूर जानती हूँ -

बिस्मिल्लाह मेरे लिए केवल एक याद नहीं हैं। वे एक रास्ता हैं। वह रास्ता जो 2006 में शुरू हुआ था और आज भी जारी है। क्योंकि कुछ रिश्तों की कोई पुण्यतिथि नहीं होती। वे याद से विरासत बन जाते हैं।

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं।

कमल पर मंडराते राजनीतिक भँवरे

कमल योगियों का प्रिय पुष्प है। योगी इस पुष्प को आधार मानकर कई रूपक गढ़ चुके हैं। हमारे शरीर में षटदल कमल की कल्पना योगियों ने ही की है। हमारा हृदय शतदल कमल जैसा है और बुद्धि में बसा हुआ ब्रह्माण्ड सहस्रदल कमल की तरह परिकल्पित है। कमल का प्रतीक पंक से ऊँचा उठने की कला सिखाता है, उसमें लिथड़ जाने की नहीं। जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूँद सूर्य के प्रकाश में उज्ज्वल झिलमिलाती है बिल्कुल उसी तरह लोकतंत्र में सबके जीवन को अपने स्वराज्य में झिलमिलाना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कर्म करते हुए संसार में लोकहित साधने का यही मुक्तिदायक उपाय है।

कमल के फूल पर राजनीतिक भँवरों को मंडराते और उसकी परिक्रमा करते देखकर इस पुष्प के कई नाम याद आते हैं.. राजीव, नीरज, पंकज और जलज भी कमल के ही नाम है। राजीवनयन, नीरजनयना और कमलनयन कहकर इस पुष्प से प्रेम से भरी उज्ज्वल आंखों की उपमा दी जाती है। पानी में उत्पन्न होने से इसे जलज कहा जाता है। पंक (कीचड़) से ऊपर उठकर खिलने से यह पंकज कहलाता है। गुण-अवगुण से सने हुए जीवन को समत्व दृष्टि से परखकर राज्यकर्ताओं और प्रजाजनों को राग-द्वेष से ऊपर उठकर कमलपत्रवत निष्काम गुजर-बसर करने की सलाह दी गयी है। राज्यसत्ता और उससे प्रतिबद्ध लोगों का अस्तित्व कमल के पत्ते पर कुछ देर के लिए ठहरी पानी की बूँदों की तरह होता है। वे अचानक ढरक जाती हैं।

कमल योगियों का प्रिय पुष्प है। योगी इस पुष्प को आधार मानकर कई रूपक गढ़ चुके हैं। हमारे शरीर में षटदल कमल की कल्पना योगियों ने ही की है। हमारा हृदय शतदल कमल जैसा है और बुद्धि में बसा हुआ ब्रह्माण्ड सहस्रदल कमल की तरह परिकल्पित है। कमल का प्रतीक पंक से ऊँचा उठने की कला सिखाता है, उसमें लिथड़ जाने की नहीं। जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूँद सूर्य के प्रकाश में उज्ज्वल झिलमिलाती है बिल्कुल उसी तरह लोकतंत्र में सबके जीवन को अपने स्वराज्य में झिलमिलाना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कर्म करते हुए संसार में लोकहित साधने का यही मुक्तिदायक उपाय है।

राजनीतिक लोगों को विभेदकारी प्रपंच के पंक(कीचड़) से ऊपर उठकर और आत्मभाव से सबको अपनाकर राज्य का संचालन कर सकना चाहिए। हाथों को भी कर-कमल की उपमा दी जाती है। देश के समूचे जीवन और उसकी आशा-आकांक्षाओं को आत्मीयतापूर्वक थामने के लिए उजले राजीवनयन और श्रम में सहकारी कर-कमल ही चाहिए। फिरंगियों से आज़ादी मिलते ही देश में रोजी-रोटी पैदा करने वाले नये उद्योगों का लोकार्पण तो राष्ट्र नायकों के करकमलों से ही हुआ है

पुराण कहते हैं कि सृष्टि का रचयिता पंक से उठी कमलनाल के सहारे ही अष्टदल कमल पर विराजमान है। आधुनिक राज्य के राजनीतिक रचनाकारों को इस बात की चिंता करना चाहिए कि यह कमल-प्रतीक राजनीतिक पंक में कहीं लिथड़ न जाये। कमल का फूल अपने से अपने में उठकर पाये जाने वाले स्वराज्य का प्रतीक है। वह सब दिशाओं में सबके खिले हुए जीवन का पहचान चिह्न है। उससे केवल वोट नहीं यह बोध प्राप्त करना चाहिए कि भारत के लोगों के कर-कमल देश के नवनिर्माण में निष्काम भाव से कैसे अपना हाथ बटायें। भेदभाव के पंक में लथपथ नेताओं के कर-कमल नहीं, लोगों के काम में लगे हुए हाथ ही देश के हालात बदल सकते हैं।

कांग्रेस ने स्व. राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

सोहागपुर। नगर कांग्रेस परिवार के तत्वावधान में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती सदभावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के पर माल्यार्पण अर्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए । कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चरित्र पर वक्ताओं ने सारगर्भित उद्बोधन दिए। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जैसवाल, आकाश चौरसिया , इलयास ख़ान,ओपी पटेल,दीपक मंडल, ऋषभ दीक्षित ,मयंक दुबे शहीद ख़ान आदि उपस्थित थे।

धड़ल्ले से जारी है रेत चोरी, निर्माण कार्य स्थलों पर अल सुबह डालते हैं रेत, दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, मामला दर्ज

सोहागपुर। धड़ल्ले से जारी है सोहागपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में रेत चोरी, निर्माण कार्य स्थलों पर अल सुबह डालते हैं, रेत, नागरिकों को सड़क पर पड़ी रेत दिखाई देती है।

वर्तमान में रेत उत्खनन परिवहन पर प्रतिबंधित है । फिर भी रेत चोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रशासन इस लगाम लगाने में नाकाम हो रहा है। इसके पीछे जो भी कारण हों। लेकिन क्षेत्र के ट्रेक्टर ट्रालियों पर निगाह रखे तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां निरंतर शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नित्य ट्रेक्टर ट्रालियों की बिक्री बढ़ रही है। क्योंकि खेत में ट्रेक्टर चलने से अधिक आमदनी रेत में हो जाती है। यहां यही कहा जा रहा है कि यह रेत नहीं यह खरा 24 केरेट का सोना है। इसी कारण हर कोई ऐसे मौके हाथ से नहीं देना चाहते हैं।

इससे सरकार को राजस्व की निरंतर हानि हो रही है। उक्त रेत की चोरी सोहागपुर तक ही सीमित नहीं है बल्कि सेमरी हरचंद,शोभापुर, माखननगर सभी जगह यही हाल है। खनिज विभाग का मुख्यालय नर्मदापुरम में है। इसका विकेन्द्रीयकरण हो तभी रेत चोरी अंकुश लगाया जा सकता है। यदि ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रीयकरण नहीं हुआ

'तो आया राम गया राम' निरंतर चलता रहेगा। हालांकि वर्तमान में खनिज अधिकारी नर्मदापुरम के प्रतिवेदन पर दो रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों के चालक एवं मालिकों पर अवैध रेत चोरी एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पहले प्रकरण में 27.7.2026 को स्वराज 735 ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 05 ए जी 7003 चालक नासिर खान सुभाष वार्ड सोहागपुर, मलिक इस्लाम खान निवासी गांधी वार्ड सोहागपुर एवं दूसरे प्रकरण में 7.8.2026 दूसरे ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड 3230 नीले रंग का ट्रैक्टर ट्राली बिना नंबर की अज्ञात चालक एवं मलिक के खिलाफ मानसून अवधि में जिले की समस्त नादियों में खनन कार्य प्रतिबंध के उपरांत भी अवैध उत्खनन परिवहन की जांच में अवैध परिवहन किया जाना पाया गया है।दोनों ही प्रकरण में धारा 303 ,2 बीएनएस एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए गए हैं। वहीं बुधवार को खनिज निरीक्षक नर्मदापुरम के द्वारा डंफर क्रमांक 04 एच ई5344 खनिज मुरम के अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर थाना पर सुरक्षा हेतु खड़ा कराया गया है।

मप्र में 2025 टीचर भर्ती की दोबारा बनेगी मेरिट

हाईकोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों की अपीलें खारिज कीं, 9693 ने गलत तरीके से लिए 5 प्रतिशत बोनस अंक

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में 5 प्रतिशत बोनस अंक के विवाद पर अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया।

कोर्ट ने कहा- आरसीआई योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल किए गए बोनस अंकों को वैध नहीं मांगा जा सकता। करीब 9,693 कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से 5त्न बोनस अंक लिए थे। हाईकोर्ट के फैसले से 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व चयन पर फिर असर पड़ेगा। अब कर्मचारी चयन मंडल आरसीआई प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करेगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद संशोधित मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मूल याचिका और रिट अपीलों में अधिवक्ता आलोक वागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की।

14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक लिए- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में 13,089 पदों पर भर्ती हुई थी। नियम के अनुसार आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5त्न बोनस अंक मिलने थे। आरोप है कि करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक ले लिए, जबकि आरसीआई के रिकॉर्ड में करीब 5,271 अभ्यर्थी ही योग्य थे। नरसिंहपुर की सोनम अगरैया और अन्य ने इसी मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

'हां' चुनने पर मिले बोनस अंक- मामले में सामने आया कि ऑनलाइन फॉर्म में आरसीआई योग्यता के सामने 'हां' चुनने पर ही बोनस अंक दे

दिए गए थे। उस समय दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी। एकलपीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के तीन मौके मिले थे। इसके बाद परिणाम आने पर 'गलती से हां चुनने' की बात स्वीकार नहीं की जा सकती।

एकलपीठ ने क्या आदेश दिया था- 6 मई 2026 को एकलपीठ ने चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल को वापस भेजने का आदेश दिया था। मंडल को आरसीआई योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देना था। इस दौरान उन्हें आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष डीएलएड डिप्लोमा अपलोड करना था।

दस्तावेजों की जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों की योग्यता सही नहीं मिलती, उनके आवेदन निरस्त करने और तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे।

अभ्यर्थियों ने क्या कहा- प्रभावित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में कहा कि उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और ऑनलाइन फॉर्म में 'हां' गलती से चुन लिया गया था। उन्होंने कहा कि बोनस अंक हटा दिए जाएं, लेकिन उनके वास्तविक अंकों के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने दिव्यांग श्रेणी का हवाला देकर राहत की मांग भी की।

हाईकोर्ट ने क्या कहा- डबल बेंच ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के तीन मौके मिले थे, लेकिन उन्होंने उस समय गलती नहीं सुधारी। कोर्ट ने माना कि परिणाम आने के बाद मेरिट में बने रहने की संभावना देखकर गलती का तर्क देना सही नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक हासिल करना धोखाधड़ी के जरिए लाभ लेना है। ऐसे लाभ को बाद में अपना अधिकार बताकर नहीं मांगा जा सकता।

दूसरे अभ्यर्थियों की मेरिट भी प्रभावित होती- कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को फिर से बदलने से उन अभ्यर्थियों की मेरिट भी प्रभावित होगी, जिन्होंने आवेदन में सही जानकारी दी थी। इसलिए गलत जानकारी के आधार पर मिले बोनस अंकों का लाभ बनाए रखना उचित नहीं होगा।

सभी अपीलें खारिज- हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एकलपीठ के 6 मई 2026 के आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक गलती नहीं पाई। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी गईं। अब आरसीआई प्रमाण-पत्रों की जांच होगी। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे।

अब क्या होगा?

- आरसीआई प्रमाण-पत्रों का सत्यापन होगा।
- अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होंगे।
- 5 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ हटाया जाएगा।
- संशोधित मेरिट सूची तैयार होगी।
- नई मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

ससुंद्रा परिवहन चेक पॉइंट ने पेश की मानवता की मिसाल

दुर्घटना के बाद हिंसा पर उतारू लोगों से बचाई ड्राइवर की जान

बैतूल। अगर आज बैतूल-1 चेक पॉइंट ससुन्दरा का स्टाफ सही समय पर नहीं आता, तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। यह कहना है गुजरात के वडोदरा से आ रहे वाहन चालक विनोद का, जिसकी गाड़ी की दुर्घटना 19 अगस्त 2026 को राजमार्ग पर हो गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन चेक पॉइंट बैतूल-1 (ससुंद्रा) के पास दुर्घटना के तुरंत बाद दूसरी कार के सवार लोग आपा खो बैठे और चालक पर हमला करने लगे। कार सवारों द्वारा चालक को निशाना बनाते हुए उसका सामान और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जा रहा था। चेक पॉइंट प्रभारी डॉ. अनामिका कोली की सतर्कता से स्टाफ ने मौके पर पहुँचकर तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पाया और ट्रक ड्राइवर को हिंसा का शिकार होने से बचाया और उसका मोबाइल भी सुरक्षित वापस बकरवाया। प्रभारी अधिकारी डॉ. अनामिका कोली ने कहा कि राजमार्ग पर यात्रा कर रहे किसी भी चालक या यात्री की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और चेक पॉइंट का अमला हर विपरीत परिस्थिति में सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। वाहन चालक विनोद का कहना है कि परिवहन चेक पॉइंट बैतूल-1 (ससुंद्रा) केवल वाहनों की जाँच और कर संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि राजमार्ग पर सुरक्षा का एक कवच भी बनते जा रहा है। उन्होंने ससुन्दरा चेक पॉइंट स्टाफ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके सहयोग के लिए सराहना की।

एसडीएम ने किया हमलापुर स्कूल का औचक निरीक्षण, बच्चों से किया संवाद

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवने के निर्देशानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल डॉ अभिजीत सिंह द्वारा शासकीय हाईस्कूल हमलापुर, जिला बैतूल का औचक निरीक्षण गुरुवार की दोपहर में किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक एवं मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने विशेष रूप से विद्यालय में उपलब्ध पेयजल व्यवस्था एवं

शौचालयों का निरीक्षण कर उनकी स्वच्छता, उपलब्धता एवं रख-रखाव की स्थिति का अवलोकन किया। डॉ अभिजीत सिंह द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति की जानकारी भी ली गई तथा विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन करावाया गया। साथ ही उन्हें व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं नैतिक मूल्यों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए नियमित अध्ययन एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया गया। उनके द्वारा विद्यालय प्रबंधन को विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

बैतूल/ कोलगांव। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांडवी में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान 2026 के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी संस्था से अर्चना दीदी एवं उषा दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। दीदियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश और समाज को कमजोर करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल दो। इससे उस देश का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो

जाता है। अर्चना दीदी ने आगे कहा कि विदेशी ताकतें देश में नशे के व्यापार को बढ़ावा देने का काम करती हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भटक जाए और देश कमजोर हो जाए। इसलिए हम सभी को जागरूक रहना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बच्चों को इस उम्र में नशा जरूर होना चाहिए, परंतु वह नशा अध्ययन का हो, जिज्ञासा को शांत करने का हो और देश सेवा का हो। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई गई। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। अंत में नशा मुक्त भारत-सशक्त भारत के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

चलती ट्रेन में महिला की तबीयत बिगड़ी, मौत

बैतूल। सिकंदराबाद से दानापुर जा रही ट्रेन में चार माह की गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महिला की नाक से खून आने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। बैतूल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मदद से महिला को ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रिंकी कुमारी (30) के रूप में हुई है। वह बिहार के बक्सर की रहने वाली थीं। वह पति हरेंद्र यादव के साथ सिकंदराबाद से दानापुर-बक्सर जा रही थीं। दोनों स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। पति हरेंद्र यादव ने बताया कि बुधवार काजीपेठ रेलवे जक्शन के पास रिंकी की तबीयत अचानक बिगडऩे लगी। उन्होंने ट्रेन में रेलवे कर्मचारियों से मदद मांगी। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हरेंद्र का आरोप है कि नागपुर स्टेशन पर उन्हें इलाज कराने के लिए कहा गया।

2 अक्टूबर से अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू

बैतूल स्टेशन पर दोनों दिशाओं में होगा ठहराव

बैतूल। बैतूल से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए नई रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। चर्लपल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 2 अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रेन का बैतूल स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा, जिससे हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रियों को सीधा रेल विकल्प मिलेगा। ट्रेन क्रमांक 22075 चर्लपल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार रात 9:45 बजे चर्लपल्ली से रवाना होगी। यह शनिवार सुबह 9:08 बजे बैतूल पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 9:10 बजे आगे रवाना होगी। ट्रेन नागपुर, भोपाल, बीना, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा होते हुए रविवार सुबह 6:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन क्रमांक 22076 गोरखपुर-चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से चलेगी। यह सोमवार सुबह 3:13 बजे बैतूल पहुंचेगी और 3:15 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी। वापसी सेवा 4 अक्टूबर से शुरू होगी। ट्रेन में स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

वर्तमान में बैतूल से सिकंदराबाद और हैदराबाद के लिए सीधी ट्रेनों की संख्या सीमित है। 12792 सिकंदराबाद एक्सप्रेस और 12722 दक्षिण एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को बैठक में दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

सोहागपुर। जनपद पंचायत कार्यालय सभागार में भारतीय निर्वाचन आयोग के एसओ श्री आजादसिंह एवं जेएसओ श्री संदीपकुमार की विशेष उपस्थिति में सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138- के बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती डॉ बबीता राठौर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शक्तिसिंह तोमर, जिला निर्वाचन सुपरवाइजर कैलाश दुबे, प्रोग्रामर अमितकुमार मिश्रा सहित निर्वाचन शाखा के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा संम्पूर्ण सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों ने बीएलओ एप् के विभिन्न मॉड्यूल एवं सुविधाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक से सारगर्भित जानकारी दी । बीएलओ एप के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों, मतदाता संबंधी जानकारी के अद्यतन, आवश्यक प्रविष्टियों तथा निर्वाचन कार्यों को ऑनलाइन एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की प्रक्रिया को समझाया गया। एसओ श्री आजाद सिंह एवं जेएसओ श्री संदीप कुमार ने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से

उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली तथा बीएलओ एप् में आने वाली तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान बताया। आपने निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रत्येक कार्य को गंभीरता, पारदर्शिता एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। ताकि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती डॉ बबीता राठौर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जा रहा है। आपने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में मतदाताओं से संबंधित कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ संपादित करें तथा किसी भी समस्या की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराएं। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शक्तिसिंह तोमर ने भी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बीएलओ एप् पर लंबित कार्यों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

जिला निर्वाचन सुपरवाइजर कैलाश दुबे एवं प्रोग्रामर अमित कुमार मिश्रा ने भी बीएलओ एप् से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं आवश्यक प्रक्रियाओं को अवगत कराया ।बैठक के अंत में भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से निर्वाचन कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों काअक्षरशः पालन करने तथा मतदाताओं को बेहतर निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। इसी अवसर पर समस्त बीएलओ द्वारा प्रदत्त सोहागपुर शिवालाय पर स्थापित प्राचीन शिव पार्वती पाषाण प्रतिमा की फोटो कृति भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों को अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर आदि ने प्रदान की।

संक्षिप्त समाचार

नैतिक शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास, अच्छे संस्कार ही बनाते हैं बेहतर समाज : भगवान भाई

ब्यावरा, निप्र। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना और संस्कारवान जीवन बनाना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ सत्य, अहिंसा, पवित्रता, करुणा, दया और आपसी स्नेह जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यह बात प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से आए राजयोगी भगवान भाई ने कही। वे बुधवार को मानस हायर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान विद्यार्थी ही भावी समाज का निर्माण करेंगे। मानवीय मूल्यों में कमी के कारण समाज में तनाव, अविश्वास, अशांति और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे समय में विद्यार्थियों को सकारात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा देना जरूरी है। प्राचार्य साकेत कुमार चंदेल ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रोड सिंह दांगी, बद्रीलाल दांगी, प्रेमशंकर शाक्यवार, रवि कुमार सहित शिक्षक मौजूद रहे। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को नकारात्मक विचारों, तनाव, व्यसनों और बुराइयों से मुक्त होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। युवाओं को क्रियात्मक, सकारात्मक, सृजनात्मक और निर्माणात्मक बनाने की आवश्यकता है। सत्य, अहिंसा, सदाचार और देशप्रेम जैसे गुणों से व्यक्तित्व निखरता है।

कमठ के उपसर्ग के बावजूद अडिग रहे भगवान : मुनि प्रवर सागर

सारंगपुर, निप्र। जैन धर्म के 23 वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस के अवसर पर आयोजित धर्मसभा में मुनि प्रवर सागर ने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान तप, त्याग, करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश दिया गया। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में आए कमठ के उपसर्ग तथा धरणेन्द्र-पद्मावती द्वारा की गई सहायता का प्रसंग भी श्रद्धालुओं को सुनाया गया। मुनिश्री ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ का जीवन विपरित परिस्थितियों में भी आत्मसंयम और समता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान पार्श्वनाथ जब तपस्या में लीन थे, तब पूर्वजन्म का बैर रखने वाले कमठ ने उनके तप में बाधा डालने के लिए भयंकर उपसर्ग किया। पत्थरों की बारिश, तेज वर्षा, आंधी के माध्यम से भगवान को विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ अपनी साधना से तनिक भी विचलित नहीं हुए।

अंकित ने नौकायन में जीते दो पदक, आईएलसीए-6 में स्वर्ण और 4 में कांस्य

राजगढ़, निप्र। खिलचीपुर के गुराड़िया निवासी अंकित सिंह सिसोदिया ने भोपाल में आयोजित तीसरी राजा भोज बहुवर्गीय नौकायन प्रतियोगिता-2026 में दो पदक जीते। 10 से 16 अगस्त तक बड़े तालाब स्थित एनएसएस परिसर में हुई प्रतियोगिता में अंकित ने आईएलसीए-6 गैर-रैंकिंग वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं आईएलसीए-4 बालक वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। अंकित वर्तमान में भोपाल पुलिस में सेवारत गोपाल सिंह सिसोदिया के पुत्र हैं।

सावित्री बनीं महिला जिलाध्यक्ष, अनीसा जिला उपाध्यक्ष

राजगढ़, निप्र। ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में संगठन की महिला पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। प्रांत अध्यक्ष सुधीर ने सावित्री गौड़ को महिला जिला अध्यक्ष और अनीसा को महिला जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर संगठन ने दोनों पदाधिकारियों से ईमानदारी के साथ दायित्व निभाते हुए संघ को आगे बढ़ाने की अपेक्षा जताई। मनोनयन पर प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जोशी, जिला अध्यक्ष स्वयं प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जगदीश गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र सोनी, संरक्षक पुरुषोत्तम शर्मा, दिलीप व्यास, कुंज बिहारी शर्मा, राजीव दुबे, संभागीय अध्यक्ष पीयूष शर्मा और राजेंद्र खत्री सहित अन्य सदस्यों ने हर्ष जताया।

मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान भुगतान अटकाया, बाबू-डिप्टी कलेक्टर को दिया गया नोटिस

राजगढ़, निप्र। जनहित से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में देरी पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सख्ती दिखाई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा प्रकरणों की वन-टू-वन समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान से जुड़े भुगतान में देरी सामने आने पर संबंधित बाबू और शाखा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर जय सोलंकी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण, जनप्रतिनिधियों के पत्र, समय-सीमा पत्रों और ई-ऑफिस में लंबित फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आई-ऑफिस में कोई फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए।

स्कूल परिसर में पौधरोपण, पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए ट्री-गार्ड

राजगढ़, निप्र। एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत फुंदिया गांव के शासकीय विद्यालय परिसर में युवा विकास विद्यालय संगठन और विद्यालय परिवार की ओर से पौधरोपण किया गया। रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए टी-गार्ड की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में पूर्व जनपद अध्यक्ष राजगढ़ एवं पूर्व भाजपा जिला महामंत्री परमानंद वर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर रामसिंह नागर, उज्जवल, युवा विकास विद्यालय संगठन अध्यक्ष आशीष नागर, शाला प्राचार्य महेश कुशवाह, जगदीश प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण साहू और शिक्षिका कौशल्या बैरागी मौजूद रहीं।

2 करोड़ की ठगी के मामले में 10 गिरफ्तार, 1.70 करोड़ बरामद

ब्यावरा, निप्र। शहर के गल्ला व्यापारी को धन दोगुना करके दो करोड़ का चूना लगाने वाले शातिर ठगों की गैंग के पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पुलिस ने अब तक बरामद की गई रकम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन करीब एक करोड़ 70 लाख की राशि बरामद होने की खबर है। पुलिस अगले एक दो दिन में बाकी रकम बरामद करने के साथ पूरे मामले का खुलासा करने की तैयारी कर रही है। दरअसल गल्ला व्यापारी देवेंद्र पालीवाल को ठग गैंग ने अपना शिकार बनाया था। धन को दोगुना करने का लालच देकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों की मानें तो गैंग के संपर्क में आने के बाद पहले व्यापारी ने पांच लाख का दांव खेला था, जिसे गैंग ने डबल करके दे दिया। जिससे व्यापारी का इस गैंग पर भरोसा जम गया था। पुलिस के मुताबिक व्यापारी ने झांसे में आने के बाद करीब डेढ़ करोड़ का लोन लेकर दो करोड़ की नगदी इस गैंग को सौंपी थी। इसके बाद ही पुलिस ने ठगी की एफआईआर दर्ज की थी। अब तक पुलिस इस मामले में देश के अलग कौने से करीब 10 लोगों को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 70 लाख की बरामदगी कर चुकी है। पुलिस गुपचुप जांच में जुटी: पुलिस ठगी की बात तो स्वीकार कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से आई इसको लेकर खुलकर कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। पहले चर्चा थी कि कुछ किसानों से व्यापारी ने उधार रकम लेकर ठगों को दी थी, अब लोन लिए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा इसमें हवाला कारोबारियों के शामिल होने की भी चर्चा पहले सामने आई थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक ठगी के मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है, वह कोई व्यापारी नहीं बल्कि फर्जी लोग हैं। इनकी गैंग लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर ठगती है। इठगी के मामले में 10 गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग कोई व्यापारी नहीं बल्कि सभी फर्जी हैं, ये पूरी गैंग है। ये लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। व्यापारी ने करीब डेढ़ करोड़ का लोन देकर ठगों को रकम दी थी। हमारे यहां ठगी की एफआईआर हुई थी, हम इसकी ही जांच कर रहे हैं।

हवाला कारोबार जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, यदि ऐसा होगा तो उसकी संबंधित विभाग जांच करेगा। शिवराज सिंह चौहान, थाना प्रभारी ब्यावरा सिटी

40 फीट गहरे कुएं में मिला महिला का शव

पिता बोले-दहेज नहीं दिया इसलिए ससुराल वालों में मार डाला, पुलिस जांच में जुटी

राजगढ़, निप्र। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव में बुधवार को महिला का शव कुएं से मिला। कुआं करीब 40 फीट गहरा है। महिला की पहचान ममता बाई सौंधिया के रूप में हुई है। पिता बिरम सिंह सोंधिया ने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना मिली कि ममता नाम की महिला सुबह 10 बजे से लापता है। कुएं के बाहर उसकी चप्पलें मिलीं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शहर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। शाम 4 बजे शव को कुएं से बाहर निकाला गया। रात लगभग 7 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर अस्पताल भेजा गया।

पिता बोले-शादी में दहेज नहीं दिया इसलिए मार दिया : परिजनों का आरोप है कि शादी के लगभग 6 महीने बाद से ही ममता को दहेज के लिए परेशान

किया जा रहा था। उसे ताने दिए जाते थे कि तेरे पिता ने शादी में दहेज नहीं दिया। परिवार ने बताया कि ससुराल वालों ने उसका मोबाइल तोड़ दिया था। जिसकी वजह से ममता बात नहीं कर पाती थी। बिरम सिंह ने बताया कि दहेज विवाद बढ़ने पर 2025 में वे ममता को अपने घर ले आए थे। लगभग 6 महीने तक मायके में रही। इसके बाद उसका पति नरेंद्र रात में अचानक ससुराल ले गया था। तब से वह ससुराल में ही रह रही थी।

अस्पताल में शव पहुंचा तो ससुराल पक्ष से कोई नहीं था : शाम करीब 7 बजे ममता का शव पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर अस्पताल पहुंचा। यहां उसके मायके पक्ष के लोग मौजूद रहे। परिजनों का आरोप है कि उस समय ससुराल पक्ष से कोई भी व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचा। शव के पास ममता की बहन और अन्य परिजन रोते-बिलखते रहे। बहन ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसकी बहन को दहेज के लिए मारकर कुएं में फेंका गया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही : पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही महिला की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हड़ताल पर डटे कृषि विस्तार अधिकारी

राजगढ़, निप्र। ई-एचआरएमएस प्रणाली में जियो-फेंसिंग से उपस्थिति दर्ज कराने सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को जिलेभर के अधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे और पूरे कार्यालय समय में प्रदर्शन किया।

कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान पर 17 से 20 अगस्त तक अधिकारी काम से दूर रहकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल से किसान कल्याण वर्ष के तहत संचालित किसानों को फसलों की जानकारी, खेतों में मार्गदर्शन और खाद वितरण भी प्रभावित हो रही है। संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा, महामंत्री सचिन परमार, जिला उपाध्यक्ष राकेश परमार, सहित अकांशा गुप्ते, शल्पा करोड, लितिका तिवारी, लक्ष्मण सिंह, योगेश त्यागी, विशाल नागर, संदीप नागर, आदि शामिल थे।

महर्षि अरविंद के राष्ट्रवाद पर हुआ व्याख्यान : राजगढ़, निप्र। महर्षि अरविंद की जयंती पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से जिला पंचायत सभागृह में जिला स्तरीय व्याख्यानमाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य ए.के. शर्मा ने महर्षि अरविंद के जीवन, राष्ट्रवाद, शिक्षा और आध्यात्मिक चिंतन पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि अरविंद केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतक और राष्ट्रवादी विचारक भी थे। उनके विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं।

2 साल से सड़क का टेंडर, काम शुरू नहीं; 6 दिन में दूसरी बार घिरी नगर पालिका

राजगढ़, निप्र। शहर की बदहाल सड़कों को लेकर नगरपालिका को मिल रहे आश्वासनों से अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। दो साल पहले टेंडर होने के बावजूद वार्ड 14 की मुख्य सड़क का निर्माण शुरू नहीं होने से नाराज रहवासी बुधवार को नगरपालिका पहुंचे और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। पार्षद मोहित तंवर के नेतृत्व में रहवासियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की। छह दिन में यह दूसरी बार है, जब सड़क और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर नगरपालिका का घेराव हुआ। वार्डवासियों ने बताया कि पुलिस परेड ग्राउंड के पीछे से बाराद्वारी मस्जिद तक करीब 28 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प योजना के तहत सड़क बनना है। इसका टेंडर करीब दो साल पहले हो चुका है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया। बारिश के बाद पूरी सड़क खुदी पड़ी है और जगह-जगह कीचड़ होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। रहवासियों ने जहरीले जीवों के घरों में घुसने का खतरा भी बताया। प्रदर्शनकारी पहले वार्ड में एकत्रित हुए और रैली के रूप में नगरपालिका पहुंचे। करीब आधे घंटे तक मुख्य गेट पर नारेबाजी के बाद सीएमओ पवन अवस्थी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रहवासियों से ज्ञापन लिया और समस्या सुनी।

स्वरोजगार के लिए महिलाओं ने सीखा हुनर, सेवा-भारती ने दिलवाया प्रशिक्षण

राजगढ, निप्र। छापीहेड़ा के देवी अहिल्याबाई प्रशिक्षण केंद्र में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सेवा भारती द्वारा संचालित केंद्र में सिलाई, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम में 180 महिलाओं को सिलाई, 35 को मेहंदी और 35 को ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष देव बाई खटीक ने प्रमाण पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह हेमंत सेठिया ने महिलाओं को प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। जिला सहसंचालक संदीप सोनी, जिला कोषाध्यक्ष शैलेंद्र विजय और सचिव मार्तंड मौजूद रहे। केंद्र का संचालन हेमा सेठिया कर रही हैं। प्रबंधक मनीष गुप्ता ने आभार माना।

नशा रोकने विद्यार्थियों ने निकाली रैली

पचोर, निप्र। 'नशामुक्त युवा, मजबूत राष्ट्र' के संदेश के साथ लायंस क्लब इंटरनेशनल और विभिन्न संस्थाओं ने नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया। पुराने बस स्टैंड पर विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से होने वाले नुकसान बताए। इसके बाद विद्यार्थियों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, स्वास्थ्य विभाग और नागरिकों ने जागरूकता रैली निकाली। समापन सभा में ब्रह्माकुमारी वैशाली दीदी ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त समाज की शपथ दिलाई। नगर परिषद अध्यक्ष विकास करोड़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित और डॉ. धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने भी नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

पांच सचिव निलंबित, चार का वेतन काटा, दो जनपद में अटैच

राजगढ़, निप्र। ग्राम पंचायतों में कर वसूली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही अब कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की। कर वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 5 पंचायत सचिवों को निलंबित, 4 कर्मचारियों के तीन दिन के वेतन काटने और 2 कर्मचारियों को जनपद पंचायत में संलग्न करने के आदेश दिए गए। समीक्षा में कई ग्राम पंचायतों में कर वसूली नहीं होने की स्थिति सामने आई। इस पर विजयगढ़ पंचायत के सचिव चंदूलाल देवड़ा और रोजगार सहायक नारायण सिंह कुशवाह, साका जागीर पंचायत के सचिव अनुप गुर्जर और रोजगार सहायक निरंजन सिंह गुर्जर के तीन-तीन दिन के वेतन काटने के आदेश दिए गए। पाडल्याबना पंचायत के रोजगार सहायक मुकेश दांगी को जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में संलग्न किया गया। समीक्षा बैठक से गायब रहने पर भी कार्रवाई चारपुरा पंचायत के रोजगार सहायक धर्मेंद्र विजयपुरिया के बिना पूर्व सूचना समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें भी जनपद में संलग्न करने के आदेश दिए गए। बूचाखेड़ी के सचिव शिवनारायण झलावा तथा मवासा के सचिव ओमप्रकाश सेन के बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और कर वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। लापरवाही और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पाडल्याबना के सचिव रमेशचंद्र मालवीय, मानपिछोड़ी के चैनसिंह चौधरी और परसूखेड़ी के गजेंद्र सिंह बैस को निलंबित किया गया।

चंदा विवाद पर दीपक शर्मा बोले- सहयोग स्वैच्छिक था, पूरा का पूरा हिसाब पारदर्शी है

राजगढ, निप्र। 84 श्री हनुमान दर्शन यात्रा के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए लेने के आरोपों पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने सफाई दी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए किसी से जबरन या प्रलोभन देकर राशि नहीं ली गई। जिन लोगों ने सहयोग किया, उन्होंने स्वेच्छा से राशि दी थी। शर्मा ने कहा कि पूर्व पार्षद भानु जकोदिया ने भी स्वेच्छा से सहयोग किया था। आरोप है कि यात्रा के सात महीने बाद हिसाब मांगने पर समिति ने जाकोदिया को मंदिर में बैठकर आय-व्यय का पूरा हिसाब दिखाने की बात कही, लेकिन वे हिसाब देखने नहीं आए। शर्मा ने कहा कि अब भी जकोदिया जब चाहें, समिति उनके साथ बैठकर पूरा हिसाब साझा करने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों के बहकावे में आकर यात्रा और समिति की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राजगढ़ के ऐतिहासिक 84 हनुमान मंदिरों को धार्मिक और पर्यटन पहचान दिलाना था।

साइकिल मिलने से छात्राओं के चेहरे खिले, स्कूल आने में होगी सहूलियत

सारंगपुर, निप्र। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को 32 छात्राओं को शासन की योजना के तहत निशुल्क साइकिल वितरित की गईं। मंत्री गौतम टेटवाल ने छात्राओं को साइकिलें प्रदान कीं। साइकिल मिलने से दूर-दराज से स्कूल आने वाली छात्राओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के तहत संचालित हेल्थ केयर और ब्यूटी वैलनेस विषय की पुस्तकों का भी राज्यमंत्री ने छात्राओं को वितरण किया। इसके बाद विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मंत्री टेटवाल ने विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षों का निरीक्षण किया।

उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर दिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, नीलेश वर्मा, निर्मल जैन, मंडल अध्यक्ष महेश पुष्पद, पार्षद और भाजपा पदाधिकारियों के साथ स्कूल स्टाफ और छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

गोरखपुरा से निकली कांवड़ यात्रा, खोयरी मंदिर में किया जलाभिषेक

राजगढ़, निप्र। गोरखपुरा से लगातार तीसरे वर्ष निकली विशाल कांवड़ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। वर्तमान सरपंच एवं यात्रा संरक्षक लोकेंद्र सिंह खींची के संरक्षण में भंवर कुंड गोरखपुरा से शुरू हुई यात्रा पैदल राजगढ़ के प्राचीन खोयरी मंदिर पहुंची। कांवड़ लेकर चल रहे श्रद्धालु पूरे रास्ते बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते रहे। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रा के दौरान गोरखपुरा के साथ करेड़ी, बरखेड़ा, नाना गांव और राजगढ़ नगर के प्रमुख चौराहों पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। कई स्थानों पर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई। लोगों ने जलपान सहित अन्य व्यवस्थाएं भी कीं। ब्रांच मैनेजर गिरिराज दांगी और उनके परिवार ने निज निवास के सामने श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने 134.97 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन प्रशासनिक संकुल भवन का किया निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में 134.97 करोड़ रुपये लागत से निर्माणाधीन कार्य नवीन प्रशासनिक संकुल भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने तथा भवन में आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को नवीन प्रशासनिक संकुल भवन की कार्य योजना एवं प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

क्षेत्रीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी संत श्री उमेशनाथ महाराज, महापौर श्री मुकेश टटवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, नगर अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल,ए डीजी श्री राकेश गुप्ता, कमिश्नर श्री आशीष सिंह,डी आई जी श्री नवनीत भसीन, एस पी श्री प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चिंता हरण गणेश के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक किए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को निर्माण की कार्य योजना की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री चिंता हरण गणेश भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कंठाल चौराहा और प्राचीन श्री सती माता मंदिर द्वार के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की डिजाइन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सती गेट से छोटा सराफा चौराहा तक पैदल भ्रमण कर मार्ग चौड़ीकरण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा ने विकास कार्य योजना की जानकारी दी।इस दौरान सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी संत श्री उमेश नाथ महाराज, महापौर श्री मुकेश टटवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, नगर अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात

मऊगंज में उफनी अष्टभुजा, 3 मजदूर फंसे, एक बहा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मऊगंज में अष्टभुजा नदी उफान पर है। बाढ़ से नईगढ़ी गांव डूब गया। यहां अमृत योजना के निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूर फंस गए, जिनमें एक तेज बहाव में बह गया। वह करीब 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा।

डिंडौरी में भारी बारिश के चलते आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं तक के स्कूल गुरुवार को बंद रहे। खरमेर नदी का पानी पुल के ऊपर आने से डिंडौरी-मंडला स्टेट हाईवे बंद हो गया है। पन्ना में भी 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश है।

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। सड़कों पर नाव चल रही हैं। गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई हैं। रीवा के निराला नगर हॉस्टल समेत 9 इलाकों में पानी भर गया। घरों और दुकानों का सामान पानी में डूब गया है।

सतना में चरवाहा नाले में बहा

सतना के भुमकहर गांव में 55 वर्षीय चरवाहा नाले में बह गया। एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट एक-एक मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।

बरगी डैम के 13 गेट खोल दिए

जबलपुर के बरगी डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में कुल 21 गेट हैं। पानी बढ़ने से भेड़ाघाट का विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात दिखाई देना बंद हो गया है।

बारिश से आई तबाही

रीवा में हुई जोरदार बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर से गुजरने वाली बीहर नदी पूरे उफान पर है। वही शहर के नाले भी उफान पर चल रहे हैं। लगातार बारिश के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नेहरू नगर, संजय नगर, गुलाब नगर, बोदाबाग, गायत्री नगर, रानीतालब सहित कई स्थानों में जल भराव होने से लोग परेशान हैं।

आधे डूब गए घर

कई घर आधे डूब गए हैं, जिसके चलते घर में रखा सामान भीग गया। वहीं, चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा बस्ती के हालात और भी ज्यादा चिंताजनक रहे हैं। यहां करीब एक दर्जन परिवार अपने घरों में फंस गए। पानी के अचानक बढ़ने से निकल नहीं पाए और पूरी बस्ती डूब गई।

छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार करते रहे

जान बचाने लोग छतों में चढ़कर मदद का इंतजार करते रहे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित निकाला है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश थम गई है, जिसके कारण अब स्थिति सामान्य बन रही है। वहीं, जिले के अधिकारी लगातार भ्रमण कर स्थितियों का जायजा ले रहे है और उचित कार्यवाही कर रहे है।

अधिकारी और कलेक्टर लगातार कर रहे हैं दौरा

बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीम सक्रिय है। साथ ही रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कई जगहों पर जाकर वहां के हालात देखें हैं। एसडीआरएफ की टीम उन्हें राहत पहुंचा रही है।

विद्युत हानि में कमी और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का उत्कृष्ट प्रदर्शन

श्योपुर, शिवपुरी संभाग– दो और राजगढ़ ने हासिल की उल्लेखनीय उपलब्धियां

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी के मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्युत हानि में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम और विद्युत सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं।

कंपनी कार्यक्षेत्र में ए.टी. एंड सी. लॉस में सर्वाधिक कमी लाने वाले वृत्तों में श्योपुर एवं शिवपुरी संभाग-दो ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। श्योपुर वृत्त द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से ए.टी. एंड सी. लॉस को गत वर्ष के 25 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025-26 में घटाकर 14 प्रतिशत किया गया। इस प्रकार ए.टी. एंड सी. लॉस में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी वृत्तों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

इसी प्रकार शिवपुरी संभाग-दो द्वारा भी ए.टी. एंड सी. लॉस में उल्लेखनीय सुधार किया गया। संभाग द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से गत वर्ष के 41 प्रतिशत ए.टी. एंड सी. लॉस को वर्ष 2025-26 में घटाकर 14 प्रतिशत किया गया। इस प्रकार 27 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज करते हुए कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी संभागों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। यह उपलब्धि विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार, प्रभावी निगरानी तथा मैदानी स्तर पर किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। विद्युत सुरक्षा के क्षेत्र में भी कंपनी द्वारा विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा मानकों के पालन, विद्युत अधोसंरचना की निगरानी तथा मैदानी स्तर पर सतर्कता बढ़ाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2025-26 में विद्युत दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। कंपनी के राजगढ़ वृत्त द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2025-26 में विद्युत दुर्घटनाओं में 68 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ सुरक्षा और दक्षता को भी समान महत्व दिया जा रहा है।

'10 साल हो गए, बेटे का अगला गुरुवार नहीं आया'

भारत भवन की मशहूर कलाकार भी वृद्धाश्रम में, बोलीं– बेटा विदेश में, अब आश्रम ही परिवार

भोपाल (नप्र)। मोतियाबिंद की समस्या थी, तब एक मिठाई वाले ने मंदिर के सामने से लाकर आश्रम छोड़ दिया। एक बार बेटा आया था और बोला- अगले गुरुवार को आऊंगा। वह फिर कभी नहीं आया...।

80 साल की अंजली श्रीवास्तव जब ये बातें कहती हैं तो उनकी आंखों में 10 साल पुराना इंतजार और बेटे के लौट आने की टिमटिमाती उम्मीद साफ झलकती है।

70 साल के कारोबारी की मौत, 4 बच्चों में से कोई नहीं पहुंचा– इंदौर के टायर ट्यूब कारोबारी घनश्याम की 4 अगस्त को भोपाल के अपना घर में मौत हो गई थी। 4 अगस्त को आश्रम में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग घनश्याम की मौत हो गई। दो दिन तक उनका शव इस उम्मीद में रखा रहा कि शायद कोई अपना आएगा। मृतक के दो बेटे और दो बेटियां हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार पुलिस और आश्रम के सेवादारों ने ही उनका

अंतिम संस्कार किया। इस घटना ने आश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्गों को अंदर तक हिला दिया।

भारत भवन की सम्मानित कलाकार– 1980 में भारत भवन जॉइन करने वाली रानी चंद्र ने रंग निर्देशक बाबा कारंत के साथ कई बड़े नाटकों में काम किया। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से पुरस्कार भी मिला था।

रेडियो व दूरदर्शन का सफर– नाटकों के बाद उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में बतौर समाचार वाचक काम किया।

विदेश में बेटा, लेकिन आश्रम ही परिवार– रानी के पति फिशरीज विभाग में डायरेक्टर थे। उनका एक बेटा विदेश में रहता है। पारिवारिक कड़वाहट के कारण उन्होंने 15 साल पहले आश्रम की राह चुनी।

रानी चंद्र का कहना है- मेरा बेटा विदेश से यहां आएगा, यह संभव नहीं है। अब माधुरी जी (आश्रम संचालिका) ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगी।

पति का मोहल्ले की भाभी से था अफेयर

पत्नी ने स्पीकर पर चला दी कॉल रिकॉर्डिंग, बदनामी के डर से महिला ने दी जान

ग्वालियर (नप्र)। जिले के पुरानी छावनी थाना इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कृष्णा नगर पहाड़ी पर रहने वाली 32 वर्षीय ममता यादव ने कथित तौर पर बदनामी से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतका के परिजनों ने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद– घटना से जुड़े तथ्यों के मुताबिक, ममता यादव की शादी करीब 15 साल पहले रामहेत यादव से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं और पति मजदूरी का काम करता है। परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ पुरानी बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग सामने आ गईं। आरोप है कि पड़ोसी और उसके परिवार के सदस्यों ने इस निजी रिकॉर्डिंग को मोबाइल के जरिए तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम पर बजाकर पूरे मोहल्ले को सुना दिया।

इज्जत उछलने से टूट चुकी थी हिम्मत– इस तरह सरेआम इज्जत उछाले जाने और बदनामी होने से ममता अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। जब 17 अगस्त को पति और बच्चे घर से बाहर थे, तब उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पति जब काम से घर लौटे तो ममता की तबीयत बिगड़ी हुई थी और पास ही जहर की शीशी पड़ी थी। उन्हें तुरंत जयारोग्य अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।

सामान्य नागरिकों के बीच ट्रेन से यात्रा कर नरेन्द्र सिंह तोमर ने रेल विकास को बताया ग्वालियर-चंबल की नई सौगात

मुरैना। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज जौरा से वीरपुर तक की यात्रा ट्रेन क्रमांक 64637 (ग्वालियर-वीरपुर मेमू) के सामान्य डिब्बे में आम यात्रियों के साथ की। उन्होंने सामान्य नागरिक की तरह यात्रियों के बीच यात्रा कर क्षेत्र में बेहतर रेल सुविधाओं के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उल्लेखनीय है कि विगत 18 अगस्त 2026 को भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कैलारस से वीरपुर तक लगभग 26 किलोमीटर लंबे रेलखंड के ब्रॉडगेज में अमान परिवर्तन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। इससे ग्वालियर-चंबल अंचल के रेल विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। ब्रॉडगेज रेल सुविधा प्रारंभ होने से क्षेत्र के ग्रामीणों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के पर्यटन एवं आर्थिक विकास को भी गति प्राप्त होगी।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण को अभूतपूर्व गति मिली है। नए रेलमार्गों का विस्तार, छोटी रेल लाइनों का ब्रॉडगेज में परिवर्तन तथा अनेक स्थानों पर दोहरी और चारहरी रेल लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के ऐसे क्षेत्रों तक भी रेल सुविधाएं पहुंच रही हैं, जहां पहले पर्याप्त रेल संपर्क उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से ग्वालियर-चंबल अंचल सहित पूरे मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज आम यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करना उनके लिए एक सुखद अनुभव है। यह यात्रा क्षेत्रवासियों के साथ जुड़ाव और रेल सुविधाओं के प्रत्यक्ष अनुभव का भी अवसर बनी।

भोपाल में पीसीसी चीफ पटवारी बोले- सरकार में आपसी खींचतान

डिब्बे कहते हैं इंजन हटाओ, इंजन कहता है डिब्बे बदल दूंगा ; प्रदेश में साइक्लोथॉन करेगी कांग्रेस

भोपाल (नप्र)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के मंत्रियों के बीच कथित खींचतान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दतिया में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के सरकारी आवास को खाली कराने के मामले को भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा ऐसी ट्रेन है, जिसमें डिब्बे कहते हैं कि इंजन हटा दो और इंजन कहता है कि डिब्बे बदल दूंगा। इस लड़ाई में भाजपा के नेता और जनता दोनों परेशान हैं।

पटवारी ने कहा कि भाजपा के बड़े-बड़े नेता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के खिलाफ दिल्ली जाते हैं

और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रोज मंत्रिमंडल में बदलाव की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह डिब्बे और इंजन की लड़ाई है। इसमें जो यात्री हैं और जनता है, दोनों परेशान हो रहे हैं।

दतिया में सरकारी आवास खाली कराने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि यह अपनी जगह है, लेकिन यदि सरकार नरोत्तम मिश्रा से इतनी ही नाराज है तो भोपाल में भी वे सरकारी आवास में रह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई हो रही है तो उनका भोपाल वाला सरकारी आवास भी खाली कराया जाना चाहिए।

स्कूलों में कांग्रेस की दस्तक, आठ दिन का अल्टीमेटम– पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को आठ दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम चलाया जाएगा। कांग्रेस के विधायक से लेकर पंचायत कांग्रेस के अध्यक्ष तक स्कूलों में जाएंगे और वहां की स्थिति सामने लाएंगे।

'भाजपा में ऊपर से नीचे तक चल रही खींचतान'

पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली का रुख कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में बदलाव की बात कर रहे हैं। पटवारी ने इसी स्थिति को 'इंजन और डिब्बे की लड़ाई' बताते हुए कहा कि इसका नुकसान सरकार के कामकाज और जनता को उठाना पड़ रहा है।

'सरकार सवाल करने वालों पर प्रहार करती है'

पटवारी ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार से सवाल करती है तो जवाब देने के बजाय प्रहार किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल करने वालों पर कार्रवाई करना इस सरकार के काम करने का तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के भविष्य की लड़ाई है और यदि युवाओं का भविष्य नहीं बचा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन करेगी कांग्रेस

पटवारी ने कहा कि यदि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कांग्रेस के आग्रह पर विचार नहीं किया तो पार्टी पूरे प्रदेश में जनजागरूकता अभियान चलाएगी। इसके तहत संभाग स्तर पर साइकिल यात्राएं यानी साइक्लोथॉन आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को शिक्षा व्यवस्था के समाधान के लिए मजबूर करेगी।

'चढ़ावे की चोरी' पर कांग्रेस का अभियान

मंदिरों में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर अलग से कार्यक्रम जारी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। उन्होंने चढ़ावे की चोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधा।

महंगाई पर पटवारी का हमला

पटवारी ने महंगाई को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि शक्कर के दाम एक साथ 16 रुपए तक बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य तेलों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सूरजमुखी, पाम, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के तेल के दाम में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दलहन के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की कॉटन मिल, नीलाम होगी

40 साल पुरानी मिल 25 करोड़ के घाटे के बाद बंद हो गई थी

खरगोन (नप्र)। खरगोन की 40 साल पुरानी जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 25 करोड़ रुपए के घाटे में जाने के बाद मिल वैश्विक मंदी से उबर नहीं पाई। नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) ने ब्याज सहित 24 करोड़ 16 लाख रुपए का बकाया निकलने पर 23 सितंबर को नीलामी तय की है। एनसीडीसी की क्षेत्रीय निदेशक इंद्रजीत कौर ने नीलामी की सूचना जारी कर दी है।

यह मिल वर्ष 2023-24 में 25.56 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने के बाद घाटे में चली गई थी। दिसंबर 2025 में इसे बंद कर दिया गया, जिससे 500 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। मिल के अंशधारियों की रकम भी फंस गई है। मिल मजदूर और कर्मचारी लेबर कोर्ट से निर्णय पारित कराकर लगभग एक करोड़ रुपए के बकाया, ग्रेच्युटी और बोनस की मांग कर रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं चेयरमैन– जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूज प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड खरगोन इस सूत मिल का संचालन कर रही है। सोसाइटी के पहले अध्यक्ष सहकारिता नेता स्व सुभाष यादव थे, जिसके बाद उनकी पत्नी दमयंती यादव चेयरपर्सन बनीं। वर्तमान में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अरुण यादव इसके चेयरमैन हैं। सूत मिल सोसाइटी पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड का भी बकाया है। 6 मई 2025 को 20 करोड़ 97 लाख 91 हजार 380 रुपए की मांग निकाली गई थी। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को एनसीडीसी ने मिल पर कब्जा ले लिया। 16 जुलाई 2026 तक यह मांग बढ़कर ब्याज सहित 24 करोड़ 16 लाख 39 हजार 17 रुपए हो गई है। यह प्रॉपर्टी 19.25 एकड़ में फैली हुई है और इसे दो हिस्सों में नीलाम किया जाएगा। प्रबंध निदेशक दीपक कट्टी ने नीलामी की पुष्टि की है।